● वर्ष-4
● अंक-182
रायपुर, मंगलवार
11 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» कुल देवी या देवता को....

भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर ईडी का छापा

भारी मात्रा में रु मिलने की खबर! नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची टीम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित पदुमनगर निवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। टीम ने आज सोमवार की तड़के भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा टीम अन्य कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आवास पर बड़ी मात्रा रुपये मिले हैं। इसके बाद ईडी की टीम घर पर नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है। फिलहाल, कितना रुपये मिला है, ये जानकारी नहीं है। संभवतः शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ईडी कागजों की जांच-पड़ताल कर रही है।

ऐसे में इस कथित शराब घोटाले में कुल कितना रुपये मिला है। यदि ये आरोप कोर्ट से सिद्ध होता है, तो ईडी की टीम अपने जांच की कार्रवाई के दौरान ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे को गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी

लखमा फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं इसी मामले में संलिप्तता के आरोप में कई अधिकारी भी जेल की हवा खा रहे हैं।

टीम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से भी पूछताछ की है। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने नेहरू नगर में मुकेश चंद्राकर और राजेंद्र साहू के घर से फाइलें जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिम कार्ड सहित 6 मोबाइल को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल से बातचीत का टीम जांच-पड़ताल करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी की जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और समर्थक रायपुर और अन्य जिलों से भिलाई निवास पहुंचकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आवास पर ही घरने पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। बंगले के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। छापामार कार्रवाई के विरोध में बंगले के बाहर कांग्रेसियों ने नगाडा बजाकर विरोध जताया। पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी भिलाई पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई को गलत बताया। वहीं यूथ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर ईडी का पुतला भी फूंका।

दूसरी ओर रायपुर में विधानसभा के कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कई सदस्यों को निलंबित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित कर सभी विधायक भूपेश बघेल के निवास भिलाई पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया।

14 ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के घर पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी कर रही है। ईडी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है। (संबंधित समाचार पृष्ठ 8 पर)

बीजेपी का कोई दखल नहीं है: सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही हैं। ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश और बीजेपी का कोई दखल नहीं है। सीएम ने कहा कि कई लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। बाकी लोग जेल जाने की तैयारी में है। यह प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जाने की नियमित जांच है। उसमें राज्य की कोई भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप पूरी तरह से गलत है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई है। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

इनके यहां चल रही ईडी की रेड

- सूत्रों के मुताबिक, भिलाई के नेहरु नगर में मनोज राजपूत
- चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह
- दुर्ग में कमल अग्रवाल किशोर राइसमिल
- दुर्ग के सुनील अग्रवाल सहेली ज्वेलर्स और बिल्डर अजय चौहान
- अन्य ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है।

माता कौशल्या व प्रभु श्रीराम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली का किया प्रार्थना

रायपुर। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के ग्राम चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने माता कौशल्या एवं प्रभु श्रीराम के समक्ष नमन करते हुए राज्य की प्रगति, जनता की मंगलकामना और सामाजिक समरसता की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित वैद्यराज सुषेण मंदिर और श्री दशरथ दरबार के भी दर्शन किए।

हंगामे से शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण

वोटर लिस्ट और एनईपी पर विपक्ष का सवाल

नईदिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आजे से शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के माध्यम से कथित तौर पर 'हिंदी' भाषा थोपे जाने को लेकर एक बार फिर टकराव देखने को मिला। डीएमके सांसदों ने केंद्र पर शिक्षा निधि रोकने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए स्कूल फंड का इस्तेमाल करना उचित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमले का जवाब दिया और विरोध करने वाले सदस्यों पर एनईपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग उठाई। वहीं, संसद के दोनों सदनों ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर द्रमुक सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दल पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।'' राहुल गांधी ने कहा, ''पूरा विपक्ष यह मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए।''

कांग्रेस के कई सदस्यों ने केरल में 'आशा' कार्यकर्ताओं के आंदोलन का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बैठक बुलाकर मामले का समाधान किया जाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, वीके श्रीकंदन और शफी परम्बिल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया।

प्रमुख समाचार

प्रधान के खिलाफ दायर किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नईदिल्ली। डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के जवाब में उनके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया। यह नोटिस एनईपी के तहत प्रस्तावित त्रि-भाषा फार्मूले पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसने केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तीव्र विवाद को जन्म दिया है। नोटिस

दाखिल करने से पहले कनिमोझी ने कहा कि डीएमके सरकार ने एनईपी पर चिंता जताई है और नीति को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कनिमोझी ने कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए फंड को ह्श्वक कार्यान्वयन से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने अपना रुख नहीं बदला है। मंत्री ने हमें झूठा और असभ्य कहा। उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप हमें असभ्य नहीं कह सकते। इससे पहले, तमिलनाडु में एनईपी के कार्यान्वयन को लेकर उठे विवाद के बीच प्रधान की टिप्पणी की कई विपक्षी सदस्यों द्वारा निंदा किए जाने के बाद लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था।

विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और सपा की राहें अलग हुई

लखनऊ। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा की राह अलग-अलग हो सकती है। सीटों को लेकर उनके बीच पेंच फंस सकता है। इसकी आशंका दोनों ही दलों के नेता जता रहे हैं। हालांकि, वे सार्वजनिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस और सपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था और इसके बेहतर परिणाम भी हासिल किए थे। लेकिन, कांग्रेस एक के बाद एक राज्य चुनाव हारती जा रही है। सपा नेताओं का मानना है कि यूपी में भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इसलिए सिर्फ लड़ने के लिए उसे सीटें नहीं दी जा सकतीं। सपा सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा ज्यादातर सीटों पर अभी से तैयारी कर रही है। अगर कांग्रेस 25-35 सीटों पर मानती है तो ठीक, वरना जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आप अलग-अलग लड़े थे, उसी तरह से यहां भी सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। यहां बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शायद ही 100 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार हो।

5वीं जेनरेशन के लड़ाकू विमान जल्द तैयार करेगा भारत

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। दूसरी तरफ दोनों दुश्मन पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों ने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। ऐसे में देश की सुरक्षा में एक-एक पल भारी पड़ रहा है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार और सेना इस जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। भारत भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। ये विमान भारत में बनेंगे और उस हर एक चीज और हथियार भारत की जरूरत के हिसाब से लगाए जाएंगे। अब भारत को फैसला करना है कि वह इस बारे में क्या फैसला लेता है। जानकार का यहां तक कहना है कि भारत और रूस मिलकर जो पांचवीं पीढ़ी के विमान बनाने की बात कर रहे हैं उसका नाम सुखोई-60 होगा, जो कई मामलों में सुखोई-57 से काफी उन्नत विमान होगा। रूस पांचवीं पीढ़ी के विमान उपलब्ध कराने में भारत की हर तरह से मदद करना चाहता है। भारत भी इसको लेकर बेहद गंभीर है। क्योंकि चीन ने अपने बेड़े में पांचवीं पीढ़ी के दो विमान शामिल कर लिया। साथ ही उसने पाकिस्तान को भी 5वीं पीढ़ी के विमान दे दिए हैं। पाकिस्तान के सैन्य बेड़े में 2029 तक ये विमान आ जाएंगे। भारत पहले से ही सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। ये 4+ पीढ़ी के बेहद घातक विमान हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में एचएएल के प्लांट में 222 विमान असेंबल किए जा चुके हैं।

60% ही होंगे चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए इस बार 60 प्रतिशत पंजीकरण ही ऑनलाइन होंगे, जबकि 40 प्रतिशत पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। इस व्यवस्था से बिना पंजीकरण आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा

के शुरुआती 15 दिन तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। यात्रा में आने के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पिछले साल बिना पंजीकरण के आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार व ऋषिकेश में पंजीकरण कराने के लिए मारामारी रही। वहीं, तीर्थ-पुरोहितों की मांग थी कि यात्रा में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। इसे देखते हुए इस बार 60 प्रतिशत पंजीकरण ऑनलाइन और 40 प्रतिशत ऑफलाइन करने का निर्णय लिया गया है। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार में 12, ऋषिकेश में 20, विकासनगर में 15, बड़कोट में दो, उत्तरकाशी में दो, हिना में दो, गुप्तकाशी में दो, श्रीनगर में दो, पांडुकेश्वर में दो और सोनप्रयाग में एक पंजीकरण केंद्र खोला जाएगा।

राम मंदिर के बाद अब सीता माता मंदिर की बारी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की और कहा कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। 'शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी वादा किया कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बिहार गया था, तो मैंने कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और यह भी कि जीवन को हर तरह से आदर्श कैसे बनाया जाए। शाह ने कहा कि गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में उनका सम्मान, सुरक्षा और स्वागत है।

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति

'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में अदानी, जिंदल और एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने किया निवेश का ऐलान

3 लाख करोड़ का निवेश, चार तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए 'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।

छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट-घंटे बिजली मिल रही है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी।

थर्मल पावर क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर

66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये लगाएगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे।

किसानों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी। इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्रमुख निवेश और योजनाएं

- परमाणु ऊर्जा: साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए रूपए 80,000 करोड़ का निवेश।
- ताप विद्युत: राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए रूपए 1,07,840 करोड़।
- सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए रूपए10,000 करोड़।
- पीएम कुसुम योजना: किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूपए 4,100 करोड़।
- पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं: ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में रूपए 57,046 करोड़।
- क्रेडा सौर पहल: सौर ऊर्जा विस्तार के लिए रूपए 3,200 करोड़।
- पीएम सूर्य योजना : राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत रूपए 6,000 करोड़।
- सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रूपए 2,500 करोड़।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली : ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए रूपए 2,600 करोड़।
- पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए रूपए 17,000 करोड़।
- आरडीएसएस (वितरण क्षेत्र योजना): वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए रूपए 10,800 करोड़।

सभापति पर गिरी अनुशासनहीनता की गाज

■ भाजपा ने किया छह साल के लिए निष्काषित, भाजपा के हितानंद को हराया

कोरबा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिह ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जहां पार्टी ने यह फैसला लिया है।

भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि नगर निगम में सभापति चुनाव को लेकर पार्टी ने अधिकृत रूप से हितानद अग्रवाल घोषित किया था जहां पार्टी के ही नूतन सिंह ठाकुर ने फॉर्म भरकर चुनाव लड़ा इसकी जानकारी प्रदेश संगठन को दी गई और उनके द्वारा नूतन सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कोरबा में नूतन सिंह ठाकुर पार्टी के सभापति के अधिकृत प्रत्याशी हितानद के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और उन्हें जीत मिली थी।

बता दें कि कोरबा नगर निगम 8 तारीख को नगर निगम सभापति के लिए चुनाव हुआ था जहां बीजेपी से अधिकृत हितानंद अग्रवाल लड़ रहे थे वही बागी होकर नूतन सिंह ठाकुर भी मैदान पर उतरे इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान भी लड़ रहे थे तीनों के बीच मुकाबला था जहां बाकी होकर लड़ रहे नूतन सिंह ठाकुर ने 33 वोट प्रकार जीत दर्ज किया।

इस संबंध में पार्षद व सभापति प्रत्याशी रहे हितानंद अग्रवाल से बातचीत की गई इस दौरान

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक नियम में चलती है और पार्टी संगठन के निर्देश पर ही कार्यकर्ता काम करते हैं उनके द्वारा जो लिया गया फैसला है वह सही है ताकि और कोई इस तरह से बगावत न कर सके।

सभापति नूतन सिह ठाकुर ने बताया कि भाजपा से निष्कासन का समाचार मिडिया के माध्यम से मिला है। हितानंद अग्रवाल जी को पार्षदो ने क्यों पसंद नहीं किया इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओ को दूंगा। मैं भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। 33 भाजपा पार्षदो ने सभापति के लिए मुझे जनादेश दिया है। सभापति के रूप में निगम के 67 पार्षदो के हितों की रक्षा करने, कोरबा शहर का चौतरफा विकास करने तथा नियमों के अनुसार निगम को चलाने का दायित्व पूरी निष्ठा से पूरा करता रहुंगा।

नए जनपद अध्यक्ष पर गिरी गाज, 6 वर्षों के लिए निष्कासित

बालोद। जिले के जनपद पंचायत गुरूर के

नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बड़ा झटका भाजपा ने दिया है। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि आज सोमवार को उनका शपथ ग्रहण है। भाजपा अब दो खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। बता दें एक नेता ईशा प्रकाश साहू की पत्नी सुभद्रा साहू को जनपद अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन सदस्यों ने सुनीता साहू को अपना समर्थन दिया। जिसके बाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई पार्टी दो भागों में बंटी हुई नजर आई। नव निर्वाचित अध्यक्ष को समर्थन और बधाई देने वालों को तुरंत व्हाट्सअप ग्रुप से निकाल दिया गया। 21 जनपद सदस्यों में से 11 ने सुनीता साहू को अपना समर्थन दिया तो वहीं 10 लोग सुभद्रा साहू के पक्ष में खड़े नजर आए, शायद कार्यकर्ता अब नए लोगों को अवसर देना चाहती है।

जिले के गुरूर जनपद का चुनाव काफी दिलचस्प था। कुल 21 जनपद सदस्यों को मतदान करना था पार्टी हालांकि सुभद्रा साहू का नाम ले रही थी। लेकिन जनपद सदस्यों के मन में सुनीता साहू का नाम था। ऐसा कहा जा सकता है जैसे पार्टी ने अपना प्रत्याशी थोप दिया था, क्योंकि उनके पति भाजपा के नेता हैं। लेकिन सदस्यों ने सुनीता साहू को अपना बहुमत देकर जिताया है। ये इस चुनाव की पहली और सबसे बड़ी क्रॉस वोटिंग की घटना रही। जिसमें भाजपा ने भाजपा को ही हराया वहीं भाजपा ने कांग्रेस के समर्थन से सुनीता साहू के अध्यक्ष बनने की बात कही। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो दोनों के लिए हुई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने वोट किसको दिया। क्योंकि जिस जनपद क्षेत्र से सुभद्रा ईषाप्रकाश जीतकर आए। वहां कांग्रेस ने पहले ही उन्हें समर्थन देते हुए कहा कि प्रत्याशी नहीं उतारा था तो कांग्रेस समर्थन का ये मामला कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है।

आपको बता दें कि जनपद पंचायत के उस चुनाव के बाद पार्टी दो भागों में बंटी हुई नजर आई। दरअसल एक खेमा सुनीता साहू के समर्थन में नजर आई तो दूसरा खेमा मायूस सुभद्रा साहू के समर्थन में बौखलाई हुई। शायद इससे पहले पार्टी ने इतना बड़ा फैसला इतनी तेजी से नहीं लिया है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि सुनीता साहू के पक्ष में एक बड़ी टीम जल्दी ही प्रदेश कार्यालय की ओर प्रस्थान कर सकती है। अध्यक्ष चुनाव में भले ही क्रॉस वोटिंग हुई लेकिन उपाध्यक्ष चुनाव में दुर्गानंद साहू निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए और उन्होंने सफलता पूर्वक उपाध्यक्ष की कुर्सी हासिल की, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें हार माला पहनाकर कार्यालय में स्वागत किया तो वहीं सुनीता साहू को बागी कहते हुए छोड़ दिया था।

गौरेला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश ने संस्कृत में ली शपथ

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। नगर पालिका परिषद गौरेला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश दुबे ने संस्कृत में शपथ लेकर सभी को अचरज में डाल दिया। इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा के 15 पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एसडीएम अमित बेक द्वारा किया गया। स अवसर पर विधायक प्रणव मरपच्ची (मरवाही) और अटल वास्तव (कोटा), भाजपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान सहित कई गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने गौरेला में भाजपा की शानदार जीत को ऐतिहासिक बतातेक कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय के सुशासन की है। गौरेला की जनता को समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया।

केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यहां एक भी नया आवास नहीं बना, जबकि भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवास निर्माण को प्राथमिकता दी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ने नमस्ते योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत नगर पालिका के कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की गई, जिससे वे सुरक्षित तरीके से सीवर सफाई कर सकें। इसके अलावा, 30 स्वच्छता दीदियों को नई वर्दियां वितरित की गईं।

नक्सल प्रभावित गांव में सोलर परियोजना घोटाला

■ ग्रामीणों ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों की हेराफेरी का लगाया आरोप

नारायणपुर। विकास के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने का दावा करने वाली प्रशासन की पोल खोलने वाला मामला ग्राम पंचायत छोटेडोंगर में सामने आया है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार वित्तीय सहायता भेजती हैं, ताकि इस पिछड़े इलाके के लोग मुख्यधारा में आ सकें। लेकिन भ्रष्टाचार का भेड़िया धसान ऐसा है कि विकास कार्यों की राशि जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जेबों में समा जाती है।

दरअसल, ग्राम पंचायत छोटेडोंगर में सोलर लाइट और सोलर पंप लगाने के नाम पर 15वें वित्त आयोग की राशि का जमकर दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत ने इस कार्य के लिए लाखों रुपये जारी किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घोटाले में फर्जी दस्तावेज बनाकर संदिग्ध तरीके से भुगतान किया गया।

छोटेडोंगर के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में शासकीय राशि का सोलर लाइट और सोलर पंप लगाने के नाम पर जमकर बंदरबांट हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पंचायत सचिव और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह सारा घोटाला हुआ। जब इस बारे में प्रशासन से शिकायत की गई, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन भी इस भ्रष्टाचार में शामिल

है? इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत इस परियोजना से जुड़े दस्तावेजों की मांग की। वहीं पंचायत ने जो कागजात दिए, उनमें कई गंभीर खामियां पाई गईं। सबसे पहले तो क्रेडा विभाग नारायणपुर का टेक्निकल सेक्शन फर्जी निकला। दस्तावेज में कोई दिनांक नहीं है और उप अभियंता, क्रेडा जिला नारायणपुर की सील लगी हुई है, लेकिन दस्तावेज की सत्यता संदिग्ध है। उक्त दस्तावेज में सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई है, और इसी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया। टीएस के अनुसार, 1000 लीटर का वाटर टैंक और 900 वॉट क्षमता का सोलर पंप लगाया जाना था। इस पर 5,80,484 रुपये की लागत दिखाई गई, लेकिन हकीकत में कार्य मानकों के विपरीत किया गया। जब इस टीएस की पुष्टि के लिए क्रेडा विभाग के अधिकारी रामकुमार ध्रुव से नवंबर 2024 में सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टीएस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त टीएस को अमान्य बताया और कहा कि जिला कार्यालय टीएस जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है, बल्कि टीएस रीजनल अथवा हेड ऑफिस से मंगवाया जाता है।

महिला नक्सलियों समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

गरियाबंद। गरियाबंद में सक्रिय तीन नक्सलियों ने आत्मसर्पण किया है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि नक्सली हथियार समेत समर्पण किया हो। एडीजी विवेकानंद सिन्हा,आईजी अमरेश मिश्रा व सीआरपीएफ के अफसरों की मौजूदगी में एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतु ने ऑटोमैटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। इनके साथ दो महिला नक्सली मंजुला उर्फ लखमी और सुनीता उर्फ जूमकी ने आत्मसर्पण किया। तीनों पर 15 लाख के इनाम थे।

आत्म समर्पण करने वाले इन नक्सलियों ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से दहशत में आकर और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्म समर्पण किया है। नुआपड़ा डिविजन कमेटी में डिप्टी कमांडर दिलीप ने बताया कि भालू डिगी की घटना के बाद से नक्सली में दहशत है। बड़े नेता भले ना आत्मसर्पण करे लेकिन छोटे नक्सली घबराए हुए हैं। किसी तरह हमें पुलिस का नंबर मिला। भागे-भागे फिर रहे थे। सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन से दबाव बढ़ा है। बार-बार डेरा बदल रहा, खाने-पीने के लिए नहीं मिलता। मुठभेड़ में मुझे गोली लगी थी, पुलिस ने इलाज कराया।

बता दें, 20 जनवरी को भालू डिगी मुठभेड़ में सीसी मेंबर चलपती और डिविजन कमांडर सत्यम गावड़े जैसे नेता समेत सवा 3 करोड़ के 16 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद जिले में बिखर चुके नक्सलियों में से महिला और एक पुरुष नक्सली ने ऑटोमैटिक हथियार के साथ आत्मसर्पण किया था। आत्म समर्पित नक्सली अब विकासशील छत्तीसगढ़ की मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन जीना चाहते हैं।

कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी 8 संदिग्धों को पकड़ा

जगदलपुर। थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में शहर के संजय बाजार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियो के द्वारा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को देखकर अपनी उपस्थित छुपाते भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पश्चिम बंगाल के निवासी आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार संदेहियो में सलमान खान पिता रजाक खान उम्र 27 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम जांशाडुम्बंर थाना तोमलु जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख मुशीबुर रहमान पिता शेख रेजाबुल हक उम्र 27 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम गोल मांगुरी थाना पांसखुरा जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख अनार अली पिता शेख अमजद अली उम्र 43 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम साधुआपोता थाना पांसखुरा जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख मैदुल स्माल पिता शेख बैसुरूदीन उम्र 32 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम जांशाडुम्बंर थाना तोमलु जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख रसीद अली पिता शेख शुक्कुर अली उम्र 30 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम चिलका थाना पांसखुरा जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख अब्दुल्ला पिता शेख रजब अली उम्र 49 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम साधुआपोता थाना पांसखुरा जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, शेख अब्दुल रहमान पिता शेख शुक्कुर अली उम्र 28 जाति मुस्लिम साल निवासी ग्राम चिलका थाना पांसखुरा जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, रजाक अली खान पिता दिदार बोक्स खान उम्र 65 साल जाति मुस्लिम निवासी ग्राम जांशाडुम्बंर थाना तोमलु जिला पूर्व मेन्दीपुर वेस्ट बंगाल, को पकड़ा गया।

जिनसे घुमने और छिपने का कारण पूछताछ करने पर सभी सही व संतोषप्रद जवाब नही देकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। सभी अनावेदकगण जो दिगर राज्य के रहने वाले है, जिनके द्वारा कभी भी किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जिसे प्रतिबंधित करने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 128 के तहत इस्तगांसा तैयार कर कार्यवाही उपरांत आज सोमवार को न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ज्वेलर्स-बिल्डर्स के ठिकानों पर भी ईडी की रेड

भिलाई। प्रंवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छत्तीसगढ़ में 15 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। इनमें कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भिलाई स्थित आवास के अलावा बिल्डर मनोज राजपूत, अजय चौहान, सहेली ज्वेलर्स के संदीप सिंह, होटल कैमलिन और दो राइस वेयर हाउस पर भी ईडी की टीमें पहुंचकर जांच कर रही हैं।वैशालीनगर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता मुकेश चंद्राकर के घर पर भी ईडी की टीम मौजूद है। सभी जगहों पर सीआरपीएफ व पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। किसी को भी अंदर बाहर नहीं होने दिया जा रहा है।

डॉ. अदिति गोविंत्रिकर ने दिए महिलाओं को सफलता के मंत्र

बिलासपुर। एसईसीएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की जानी-मानी हस्ती, कॉर्पोरेट कोच, अभिनेत्री एवं भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड डॉ. अदिति गोविंत्रिकर ने महिलाओं को सफलता के मंत्र विषय पर एक विशेष वर्कशॉप ली। कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी संचालन सह योजना/ परियोजना, श्री एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) श्री बिरंची दास, निदेशक (वित्त) श्री डी सुनील कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिला कर्मी उपस्थित रहे। डॉ. अदिति गोविंत्रिकर ने अपनी वर्कशॉप में महिलाओं को खुद पर भरोसा रखने, आत्मनिर्भर बनने और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत पर बल दिया इस अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

ग्रामीणों ने उठाया जंगल की सुरक्षा का बीड़ा

लोरमी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अचानकमार अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व (ञक्र) क्षेत्र के वनग्राम निवासखार के ग्रामीणों ने वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। यहां के ग्रामीणों ने ञक्रप्रबंधन के साथ मिलकर जंगल को अवैध कटाई, अतिक्रमण और आगजनी से बचाने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। बता दें कि सोमवार सुबह सुरही परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम निवासखार में ग्रामीणों ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत जंगल की सुरक्षा का संकल्प लिया। ग्राम सरपंच रामकुमार आर्मो की अध्यक्षता और सामुदायिक वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रहलाद सिंह की पहल पर हुई इस बैठक में 200 से अधिक ग्रामीण (महिला और पुरुष) शामिल हुए। बैठक में जंगल संरक्षण के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में उपस्थित परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार को ग्रामीणों ने भू-अभिलेख में सुधार करने की मांग की। साथ ही पुराने वनरक्षक भवन को सामुदायिक वन प्रबंधन समिति को सौंपने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।

ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से जुर्माने की वसूली की

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर। शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मनेंद्रगढ़ में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए 38 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में सिटी कोतवाली पुलिस, आरटीओ विभाग, राजस्व विभाग और नगरपालिका की टीम संयुक्त रूप से शामिल रही। एसडीएम, तहसीलदार और एनएच विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, ओवरलोडिंग और रेड लाइट जंप जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। एसआई सतेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से चलाया गया है। भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें।

धमतरी के सेमरा गांव में होली से 7 दिन पहले मना त्योहार

धमतरी। देशभर में 14 मार्च को होली त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है, जहां रविवार को पूरे गांव वालों ने होली का त्योहार मना लिया। शनिवार को होलिका दहन हुआ और इसके दूसरे दिन रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। अनोखी परंपरा को निभाने वाले इस गांव का नाम सेमरा है। रविवार को इस गांव में होली मनाई गई। तिथि से पहले मनाई गई इस होली की चर्चा पूरे देश में है। होली पर आसपास के गांव के लोग भी मेहमान के तौर पर सेमर गांव पहुंचे और रंगों का त्योहार मनाया। गांव में रंग, गुलाल और पिचकारियों का बाजार सजा। घर घर में पकवान बनाए गए। लोगों ने होली का खूब आनंद लिया। स्थानीय कामता निषाद ने कहा हमारे गांव में होली मनाई जा रही है। हमारे गांव की परंपरा है। इस वजह से होली की तिथि से एक हफ्ते पहले होली मनाते हैं। होली को लेकर गांव में काफी उत्साह है। होली के साथ साथ दिवाली, हरेली, पोला भी हफ्तेभर पहले मनाते हैं।

वन विभाग की लापरवाही, जंगलों में नहीं रुक रही पेड़ों अवैध कटाई

■ डीएफओ ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के आदिवासीय क्षेत्र बीजापुर, जहां पेड़ों को भगवान स्वरूप पूजा जाता है। जहां आदिवासी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन करते हुए मर मिटते हैं, ऐसी जगह पर जिन अधिकारियों पर जंगलों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, उनके नाक के नीचे लगातार कुटरू वन परिक्षेत्र (बफर) के वनों में अवैध कटाई जारी है और वे कुंभकरण की नींद सो रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं। जबकि वन विभाग अवैध कटाई करने वालों पर को सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीट नैमेड़ के नयापारा में वनों की अवैध कटाई पर विभाग अंकुश नहीं लग पा रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि बीट नैमेड़ के नयापारा क्षेत्र में जंगलों को खेती किसानी के लिए साफ किया जा रहा है। इसमें ऐसे पेड़ों को भी ग्रामीण काट रहे हैं, जिन्हें कुछ साल पहले ही रोपा गया था। कई स्थानीय लोगों द्वारा विभागीय अधिकारियों से भी इसकी शिकायत करने पर भी विभाग के रेंजर से लेकर बीट गार्ड के कानों में जूं तक नही रेंग रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग समेत कई जिम्मेदारों को इस अवैध कारोबार के बारे में जानकारी है, लेकिन इस संबंध में पूछे जाने पर ऐसी गतिविधियों के होने से नकार दिया जाता है। यदा कदा विभाग के द्वारा ग्रामीणों की सजगता एवं सूचना पर लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई की जाती है। उनमें से भी पुख्ता कार्रवाई के अभाव में दोषी बच निकलते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि अवैध कटाई से क्षेत्र के जंगल उजड़ रहे हैं। जंगलों से इमारती लकड़ी के साथ-साथ अवैध जलाऊ लकड़ी का कारोबार भी दिनोंदिन फल फूल रहा है। इन लकड़ियों का प्रयोग होटलों, ढाबों, ईंट भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है।

हाल ही में कुटरू वन परिक्षेत्र के बीच जंगल कटाई देखने को मिली। वहीं नैमेड़ बीट के नयापारा के बीच जंगल कटाई के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहां कुछ ग्रामीण जहां जंगलों की कटाई कर रहे हैं। वहीं जंगल साफ कर खेती करने और जमीन अतिक्रमण पर भी लोगों में आपसी विवाद हो रहे हैं।

कब्जा का कारण खेती करने और पट्टों का लालच

कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नैमेड़ आदिवासी समुदाय की आड़ में वन माफिया काम करता है। वह उनसे जमीन साफ करवाकर उस पर कब्जा करके खेती करता है। आदिवासी समुदाय गरीब का गरीब बना रहता है। उनका कहना है कि गांव वाले यह समझने लगे हैं कि वनों पर उनकी जिंदगी निर्भर है। अगर वे न रहे तो न तो मवेशियों को चराने के लिए जगह बचेगी न ही बारिश होगी। इसके लिए ग्रामीण भी पहल कर चुके हैं। लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से जंगल कटाई नहीं रुक पा रही है। वहीं पट्टों के लालच में भी कई ग्रामीण कब्जे करने जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

इस पूरे मामले में जब परिक्षेत्र रेंजर रामायण मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पहले भी जंगल कट चुका है, ग्रामीणों को समझाने पर भी नही समझते हैं, उसमें विभाग क्या करेगा।

हालांकि इसके बाद इंद्रावती डीएफओ संदीप बल्गा ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मैं वहां स्टाफ भेजकर जांच करवाता हूं और जो भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोयले से भरा ट्रक पलटा, हाईवे पर लंबा जाम

गौरेला पेंड्रा मरवाही। बिलासपुर पेंड्रा हाईवे पर एक कोयले से भरा ट्रक पलट गया।जिससे रोड पर दोनों ओर जाम लग गया। ट्रक चालकों की मानें तो रोड जर्जर होने के कारण हादसा हुआ है। हादसा होने के बाद सड़क के दोनों ओर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। जब बंजारी घाट पर कोयले से भरा ट्रेलर जर्जर सड़क होने के कारण पलट गया।हादसे में ट्रक का चालक बाल-बाल बच गया।लेकिन सड़क पर कोयला बिखरने पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।जिसके कारण भारी वाहनों समेत यात्री बसें जाम में फंस गईं। आपको बता दें कि सड़क केंवची से रतनपुर नेशनल हाईवे में स्थानांतरित हो गया है। निर्माण कार्य भी कुछ जगहों पर चल रहा है।

आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि ठेकेदार और यातायात विभाग परिवहन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहा है। इस वजह से सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पेंड्रा की ओर से बिलासपुर जाने वाले वाहन किसी तरह धीरे-धीरे करके थोड़ी बहुत जगह मिलने पर निकल रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया महतारी वंदन कॉमिक्स का विमोचन

रायपुर। महिलाओं के सम्मान और

सशक्तिकरण को समर्पित महतारी वंदन योजना पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित महतारी वंदन अभिनंदन समारोह में महतारी वंदन कॉमिक्स का विमोचन किया। यह कॉमिक्स महतारी वंदन योजना की उपलब्धियों और इसके प्रभाव को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल को योजना के उद्देश्य और जनसंदेश को व्यापक रूप से पहुँचाने का अभिनव प्रयास बताया। समारोह में कार्टून वॉच इंडिया की श्रीमती आरती शर्मा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस कॉमिक्स के निर्माण में अहम योगदान दिया। इस कॉमिक्स के माध्यम से महतारी वंदन योजना की सफलता को सृजनात्मक तरीके से दर्शाया गया है, जिससे यह योजना की लाभार्थी महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय क्रिकेट टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी में जीत पर दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में शानदार जीत की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। दुबई में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और दृढ़ संकल्प की जीत करार दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय टीम के जुझारूपन, अनुशासन और टीम वर्क की सराहना करते हुए कहा कि बारह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने टीम इंडिया को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले वर्षों में भी इसी जोश और जज्बे के साथ देश को गौरवान्वित करती रहेगी।

छत्तीसगढ़ में छावा हुआ टैक्स फ्री, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। राज्य शासन हिन्दी फीचर फिल्म छावा के कथानक एवं अन्य विशेष गुणों को दृष्टिगत रखते हुए फीचर फिल्म के छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन की अवधि दिनांक 27.02.2025 से छः माह तक के लिए इस सेवा प्रदाय पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) के अधीन देय राज्य माल और सेवा कर. (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान करने का आदेश देता है। इस प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स द्वारा राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकट का विक्रय किया जायेगा। इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। इस सेवा के प्रदाता मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर द्वारा इस सेवा पर देय राज्य माल एवं सेवा कर की राशि का स्वयं वहन किया जायेगा। इस सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2040 के अंतर्गत विकलनीय होगी। इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए जाएंगे।

बीसीसीआई कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह ने टीम इंडिया को दी बधाई

रायपुर। दुबई में रविवार को चैंपियंस ट्राफी 2025 की शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह ने अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की है। टूर्नामेंट के दौरान वे स्वंय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह,बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और अन्य पदाधिकारियों के साथ खिलाडियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। उन्होने जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा कि चैंपियंस ट्राफी में भारतीय टीम का पहले ही मैच में प्रदर्शन को देखकर लग रहा था कि टीम पूरी तरह से अपने लय में हैं। इसीलिए फाइनल मैच जीतने तक वह अजेय रही। टीम नेटवर्क,बेहतर समन्वय,कप्तान रोहित शर्मा का कुशल नेतृत्व से टीम ने यह जीत हासिल की है। चैंपियंस ट्राफी 2025 की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज भी भारतीय क्रिकेट टीम विश्व क्रिकेट का सिरमौर है।

युवा समाज सेवी तृप्ति लुनिया का डॉक्टरेट की उपाधि से हुआ सम्मान

रायपुर। हरिहर धाम, सोनपुर, पटना में आयोजित एक समारोह में शहर की युवा समाजसेवी तृप्ति लुनिया को थावे विद्यापीठ, गोपालगंज, बिहार द्वारा सम्मानित किया गया है। तृप्ति लुनिया पिछले 10 वर्षों से शहर में एक समाज सेवी के रूप में जानी जाती हैं, जो गौ सेवा, बुजुर्गों की सेवा, मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाना, पेंटिंग और अन्य कौशलों का निःशुल्क प्रशिक्षण देने में लगी हुई हैं। इसके अलावा, वह कुत्तों और अन्य पशुओं की देखभाल करने में भी सक्रिय हैं, जिनमें विशेष रूप से विकलांग और निराश्रित जानवर शामिल हैं।

ईडी रेड पर सियासत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला

कहा- ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अगर कुछ नहीं किया तो डर नहीं होना चाहिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई से सियायत तेज हो गई है। पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया है। तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे सोर्स के आधार पर कार्रवाई होना बताया है।

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पूर्व सीएम बघेल के घर ईडी के छापे की कार्रवाई पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ। ईडी सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है। किसी किस्म का दोष पाया जाएगा तो निश्चित दोषी करार होंगे। कुछ नहीं किया हो तो डर नहीं होना चाहिए, ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है। जहां गड़बड़ी होती है वहां जांच करती है।

चरणदास महंत का भाजपा पर हमला

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, छत्तीसगढ़िया पूर्व मुख्यमंत्री एआईसीसी राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई सत्तारुढ भाजपा के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण

राजनीति का एक और उदाहरण है। भाजपा ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनितिक लाभ के लिये कर रही है, जो लोकतंत्र के लिये खतरा है, ये गलत परम्परा है।

चरणदास महंत ने कहा कि सभी कांग्रेसजन भूपेश बघेल के साथ है और इससे डरने वाले नहीं हैं, बापू के मार्गदर्शन सत्य अहिंसा को मानने वाले लोग है इस संघर्ष को परास्त करके रहेंगे।

लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं : टीएस सिंहदेव

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के रूप में कार्य कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध की गई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का सुनियोजित प्रयास है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इस अन्याय के विरोध में धरातल पर उतरते हुए भिलाई के लिए रवाना हो गया हूं। मैं इस विषय को लेकर पार्टी के विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के अन्य जिम्मेदार साथियों के सतत संपर्क में हूं और हम सब एकजुट होकर इस लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे और जनता की आवाज़ पर हमला है।

पूरा देश जानता है कि भूपेश के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए

छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई-3 स्थित निवास पर छापेमारी की है। इसके अलावा

जांच एजेंसी ने कुल 14 ठिकानों पर दबिश दी, जहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। श्वष्ठ की छापेमारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में कई बड़े-बड़े घोटाले हुए। जांच चल रही है, भूपेश बघेल के करीबी लोगों की घोटाले में प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है। वो गिरफ्तार भी हैं उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है, ये ईडी की जांच के कारवाई का हिस्सा है। अगर भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया है, उनकी कोई भूमिका नहीं हैं, तो उन्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है।

सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह छापेमारी किस विशेष मामले से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही वे ईडी के रडार पर थे।

पायलट ने पूर्व सीएम के घर ईडी छापे को लेकर सरकार पर साधा निशाना

भूपेश बघेल के घर ईडी छापे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री @bhupesh-baghel के यहां ईडी का छापा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। भाजपा ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग अब एक सुनियोजित ढर्रा बन चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुचलने और धमकाने वाली राजनीति अब एक पैटर्न बन गई है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा साबित हो रही है। कांग्रेसजन इससे डरने वाले नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक जीवन ज्योति योजना ने बदली किसानों की तकदीर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और राज्य के लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, लेकिन बिजली की बढ़ती लागत, सिंचाई के साधनों की कमी और खेती में आधुनिक तकनीकों की अनुपलब्धता के कारण किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों की इन समस्याओं को हल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस योजना ने न केवल किसानों को निःशुल्क और रियायती बिजली प्रदान की, बल्कि कृषि उत्पादन में भी सुधार किया। यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे उनकी उत्पादन लागत कम हुई, उनकी आय में वृद्धि हुई और वे अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं।

कृषक जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क और रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर सिंचाई और कृषि कार्य कर सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएं

5 हॉर्स पावर (एचपी) तक के पंपों को निःशुल्क बिजली- इससे छोटे और सीमांत किसानों को भारी लाभ मिला। 5 एचपी से अधिक के पंपों के लिए रियायती दरें - इससे बड़े किसानों को भी राहत मिली। बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार - पुराने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना। सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना - जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध कराए गए। ऑनलाइन आवेदन और मॉनिटरिंग सिस्टम - किसानों को पारदर्शी और तेज़ सेवाएँ देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।

अभी तक नहीं थमा अवैध शराब बिक्री

■ नवनिर्वाचित पंचायत ने भी ज्ञापन सौंप खोला मोर्चा

रायपुर। संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान ही पूर्ववर्ती पंचायत द्वारा पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री से मुक्ति दिलाने के गुहार के बाद भी सकारात्मक परिणाम न मिलने से आक्रोशित पिपरहट्टा के नवनिर्वाचित पंचायत ने आंदोलनात्मक रुख अपनाने के पहले एक बार फिर ध्यानाकर्षण कराने का निर्णय ले पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप इस पर पुख्ता रोक लगाने व लिप्त तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की है। इधर शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने सौंपे ज्ञापन में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्रामों में बिक रहे अवैध शराब, गांजा व नशीली गोलियों सहित जुआ पर रोक लगाने सतत् सघन प्रभावी कार्यवाही की मांग की है।

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1500 की आबादी वाले ग्राम पिपरहट्टा में बेखौफ अवैध शराब बिक्री से ग्रामीण त्रस्त हैं।

ग्रामीणों के अनुसार खासकर एक पुलिसिया रिकार्डधारी असामाजिक तत्व के द्वारा बेखौफ अवैध शराब बिक्री करने व उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से उसे राजनीतिक अथवा प्रशासनिक संरक्षण मिलने की भी आशंका ग्रामवासी व्यक्त करते हैं। नजदीकी ग्राम तोडगांव , गोढ़ी व सिवनी के पियक्कड़ों का मजमा इसके यहां लगने की जानकारी ग्रामीण देते हैं और खासकर सुबह - सुबह-सुबह व शाम ढले। बीते शुक्रवार को पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा लाल उमेद सिंह से मुलाकात न हो पाने पर उनके कार्यालय को व पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के कार्यालय में पदस्थ पुलिस अधिकारी चंचल तिवारी को सौंप हालात से अवगत कराया गया। इधर आज सोमवार को श्री शर्मा के साथ गये एक प्रतिनिधिमंडल मंडल ने थाना प्रभारी अविनाश सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप हर हाल में अवैध शराब बिक्री बंद कराने की मांग की। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस जी के गृह ग्राम होने के कारण ग्रामीणों ने उनसे भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

इधर बीते 6 मार्च को श्री शर्मा ने इन तीनों अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में क्षेत्र में चल रहे असामाजिक गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने पुख्ता कार्यवाही करने व आसन्न होली त्यौहार के? परिपेक्ष्य में असामाजिक तत्वों पर फौरी लगाम कसने का आग्रह किया है ताकि ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मना सकें। प्रतिनिधिमंडल में नवनिर्वाचित सरपंच कुंजबिहारी वर्मा , संदीप वर्मा, परमानंद ठाकुर व अनिल वर्मा आदि शामिल थे।

प्रधानमंत्री 30 को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ आयेंगे

केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन और उप मुख्यमंत्री साव ने तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 30 मार्च को बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ आ रहें हैं। बिलासपुर में कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बिल्हा के ग्राम मोहभट्ठा में प्रधानमंत्री की विशाल आमसभा होगी। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रविवार को स्थल निरीक्षण कर इसकी तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। विधायकगण सर्वश्री धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री अवनीश शरण और एसपी श्री रजनेश सिंह सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अफसर भी इस दौरान मौजूद थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मैदान के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए चिन्हांकित स्थलों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की सौगात लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आसपास रहने वाले लोगों को भी किसी तरह की परेशानी न हो। सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी है।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री साहू और उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मैदान के हर कोने का भ्रमण कर बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपेड, मंच, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। डीएफओ श्री सत्यदेव शर्मा, बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री अमित कुमार तथा जिला पंचायत के सीईओ एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित आमसभा की तैयारी से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी

■ 12 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

रायपुर। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। इच्छुक युवा 12 मार्च से अपना ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट http://www.joinindian-army.nic.in/ पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमेन (8वीं एवं 10वीं), महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। इच्छुक युवा सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया 12 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं।

अभ्यार्थी अग्निवीर के दो पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते है। अग्निवीर क्लर्क के अभ्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा सीईई के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा सीईई जून 2025 मे होने की संभावना है।

किसी भी अन्य जानकारी और समस्या के लिए युवा सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलिफोन नंबर 0771-2965212/0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर की जाती है। इसलिए किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के झांसे में न आए।

छत्तीसगढ़ कुनबी समाज महासंगठन ने फिल्म छावा को कर मुक्त करने पर किया आभार प्रकट

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुनबी समाज महासंगठन के 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट कर, छत्रपति शंभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को राज्य में कर मुक्त किए जाने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह निर्णय इतिहास को सहज और सरल रूप में जन-जन तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण पहल है।

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, मराठी टोपी, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा कहा कि आपके नेतृत्व में प्रदेश सुशासन और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने शिवाजी जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल की महिला सदस्यों श्रीमती सारिका गेडेकर व श्रीमती मनिषा बारसे ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि कुनबी समाज की महिलाओं ने सामाजिक भवन में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना की है। इसके तहत हल्दी, मिर्च, मसाले आदि का निर्माण और पैकेजिंग कर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला पत्रकारों का किया सम्मान

महिला पत्रकारों ने साझा किए अपने अनुभव और चुनौतियाँ, मुख्यमंत्री के साथ लंच और सेल्फी भी ली

रायपुर। मुख्यमत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित महतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर चर्चा की। महिला पत्रकारों ने कहा कि महिला पत्रकार राजनीति, अपराध, खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें बराबरी का अवसर मिले।

उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की सराहना की और कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से दूर भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। इससे अब अभिभावक अपनी बेटियों के करियर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने

पत्रकारों की सम्मान निधि ?10,000 से बढ़ाकर ?20,000 करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह आयोजित करने पर खुशी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता ने हमें अपने घर बुलाया हो। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाएँ समाज निर्माण की सशक्त धुरी हैं, और महिला पत्रकार अपनी लेखनी से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री श्री साय के साथ लंच किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला पत्रकारों के लिए भविष्य में नई योजनाओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार महिला पत्रकारों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिसीमन की आड़ में विभाजन की राजनीति

विराग गुप्ता

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन की आड़ में उत्तर और दक्षिण के साथ भाषा के नाम पर विभाजनकारी सियासत शुरू कर दी है। संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों को समानता के आधार पर एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए हर जनगणना के बाद संसद और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनका परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। उस समय 54.8 करोड़ की आबादी में लगभग 10 लाख लोगों के भौगोलिक क्षेत्र से एक सांसद का निर्धारण किया गया था। अब 54 साल बाद आबादी बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। इसीलिए नए संसद भवन में लगभग 848 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा हुआ, तो हर 17 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पूर्व चीफ जस्टिस ललित ने कहा है कि 'एक देश-एक चुनाव' से जुड़े संघीय मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। इसलिए स्टालिन की सियासी मुहिम के पीछे अनेक जटिल सांविधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों का लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पिछले 54 साल में आबादी 54 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। ऐसे में अगर सांसदों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया, तो संसदीय प्रणाली में सांविधानिक असंतुलन बढ़ सकता है। वोट पाने के लिए नेता लोग विभाजनकारी सियासत करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के पक्ष में विकास और गवर्नेंस के मजबूत तर्क हैं। उत्तर के चार राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की 174 सीटें हैं, जो कुल सांसदों की 32 फीसदी हैं। जबकि दक्षिण भारत के पांच राज्यों-तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कनार्टक में 129 (24 फीसदी) सीटें हैं। सीटें बढ़ाए बगैर अगर 543 सीटों का 2026 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ, तो उत्तर के चार राज्यों में 31 सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। जबकि दक्षिण के पांच राज्यों में 26 सीटें घटकर 103 हो सकती हैं। देश में जन्मदर के आंकड़ों के अनुसार, अगले तीस वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि का दौर खत्म हो सकता है। इसलिए स्टालिन अगले तीस वर्षों पर 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को जारी रखना चाहते हैं। मध्य मार्ग अपनाते हुए कुछेक लोग विधानसभा की सीटों का नवीनतम जनगणना के अनुसार परिसीमन करने का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने पर राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों और सांसदों के मतों का मान और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में बड़ा असंतुलन हो सकता है। आजाद भारत में 1951 की पहली जनगणना के बाद 1952 में परिसीमन आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया था। उसके बाद 1962 और 1972 में परिसीमन किया गया। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से सरकार ने 2001 की जनगणना होने तक लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया। उसके बाद वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून मंत्री अरुण जेटली ने समय सीमा को 25 साल आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया। लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सीटों के परिसीमन को 1991 की जनगणना के अनुसार किया गया। अब 2026 की जनगणना के अनुसार, परिसीमन करने पर सांसदों की संख्या बढ़ाकर 848 की जाएगी, तो उत्तर के चार राज्यों में लगभग 150 सीटें बढ़कर कुल 324 हो जाएंगी। दूसरी तरफ, दक्षिण के राज्यों में सिर्फ 35 सीटें बढ़ेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि समानुपातिक आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन स्टालिन ने केंद्र से सवाल किया है कि समानुपातिक गणना के लिए किस आधार का इस्तेमाल होगा। परिसीमन, महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना के संवेदनशील विषय जुड़ते जाने से जनगणना में लगातार विलंब हो रहा है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जनगणना पर 8,754 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था, जो अब काफी बढ़ गया होगा। इस बार बजट में जनगणना के मद में सिर्फ 574 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो कुल खर्च के छह फीसदी से कम है। लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में 106वें संविधान संशोधन के कानून का भविष्य भी अधर में लटका है।

बिहार में हिंदुत्व की समां बंधने से सियासी दलों की बेचैनी बढ़ी

कमलेश पांडे

बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर-नवम्बर महीने में होंगे। हालांकि, उससे महीनों पहले राज्य में धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कहीं एनडीए और यूपीए एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते प्रतीत हो रहे हैं तो कहीं उनके गठबंधन के अपने ही साथी एक-दूसरे को रणनीतिक मात देते हुए अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर बेताब नजर आ रहे हैं। इस नजरिए से भाजपा-जदयू की धींगामुश्ती और राजद-कांग्रेस की अंदरूनी कुश्ती के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सबके बने बनाए खेल बिगाड़ रही है।

एक तरफ जहां धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के वोटों का बिखराव तय माना जा रहा है, वहीं हिंदुत्व का नया जनज्वार यहां भी पैदा होती दिखाई दे रही है। इससे जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके समर्थक ज्यादा परेशान हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जब अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे, तो रही सही कसर पूरी हो गई। क्योंकि उनका हुर्मुठ धार्मिक अंदाज बिहारियों पर भी अपना छाप छोड़ेगा ही।

उधर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुपौल में और आर्ट ऑफ लिविंग के श्रीश्री रविशंकर भी पटना में यानी राज्य में मौजूद हैं। इससे धीरेंद्र शास्त्री के गोपालगंज में पांच दिवसीय हनुमंत कथा की समां बंध चुकी है। वहीं, बिहार में हिंदुत्व की समां बंधने से सियासी दलों की बेचैनी भी बढ़ चुकी है। दरअसल, अपने हिंदुत्व का बिगुल फूंकते हुए बागेश्वरधाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि वह किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं बल्कि हिन्दू धर्म के विचारक हैं।

पंडित शास्त्री का यह कहना कि वह अब सनातनियों को झुकने नहीं देंगे, हिंदुओं की आबादी घटने नहीं देंगे, और भारत के पहले ही बहुत टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए अब भारत के और टुकड़े होने नहीं देंगे, को सुनकर हिन्दू गदगद हैं। वहीं, पंडित शास्त्री ने सवालिया लहजे में यह पूछकर अपना धार्मिक एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि ईसाइयों के हितचिंतक 95 देश हैं, इस्लामी मतावलंबियों यानी मुसलमानों के हितचिंतक 65 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का हितचिंतक कौन देश है?

उन्होंने अपनी चिंता प्रकट करते हुए आगे कहा कि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम आदि देशों में जो 150 करोड़ हिन्दू हैं, जो दुनिया की तीसरी

बड़ी धार्मिक आबादी है, उनका हितचिंतक तो अखंड भारत के ही देशों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम डंके की चोट पर उनसे हिंदुत्व से जुड़े ये कार्य करवाएंगे, लेकिन हिंदुओं का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि हम हिंदुओं के लिए ही जीयेंगे और हिंदुओं के लिए ही मरेंगे। इसलिए हम पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में घूम-घूम कर हिंदुत्व का अलख जगा रहे हैं।मुझे बिहार के लोगों से ज्यादा उम्मीद है। हिन्दू राष्ट्र की मजबूत हुंकार इसी क्रांतिकारी भूमि से भरी जाएगी।

स्वाभाविक है कि बिहार में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का एक धार्मिक नेता वाला अवतार दिखा। इससे पहले वह उड़ीसा, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों को भी हिंदुत्व और भारतीयता के लिहाज से जगाते चले आ रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, यदि इसमें भक्ति ना हो तो वह किसी काम की नहीं। जीवन में भक्त और भक्ति एक दूसरे के बिना सफलता की कामना संभव नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा, जीवन में सबका सम्मान करें। छोटे से छोटे व्यक्ति भी सम्मान के पात्र होते हैं। जीवन के कर्तव्यों के साथ-साथ भक्ति भी जरूरी है। भक्ति के बिना सफल जीवन की कामना बेकार है।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, भारत को बंटने नहीं देंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। उन्होंने कथा के दौरान ही कहा, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, बल्कि हिंदुत्व के विचारक हैं। यह देश हमारा है, यह बिहार हमारा है। हम हिंदुत्व जगाने आए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। उन्होंने दुनिया में अलग-अलग देश में रह रहे अलग-अलग समुदाय के साथ हिंदुत्व पर चर्चा करते हुए भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बताया। उन्होंने कहा, हम हिंदू को एकजुट करने आए हैं। आप हमें रामनगर में जब तक रखेंगे हम तब तक रहेंगे। पांच दिवस ही क्या, पांच महीने तक हम हिंदुत्व के लिए कथा करते रहेंगे। विदेश से भी श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंचे हैं। इससे बागेश्वरधाम सरकार श्री शास्त्री की लोकप्रियता और भी परवान चढ़ने लगीहै।

चूंकि बिहार राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। इस लिहाज से मार्च के पहले-दूसरे सप्ताह में, वो भी होली से ठीक पहले बिहार में एक साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर का दौरा करना महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से सजग रहे बिहार में हिंदुत्व का एक नया उफान पैदा होगा, जिससे सूबे में भाजपा की जड़ें और मजबूती से जमेंगी।

चूंकि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में जीत चुकी भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव में मुंहकी खा चुकी है। इसलिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को वह हर हाल में जीतना चाहती है। चूंकि वह यहां पर जदयू के साथ चुनाव लड़ती आई है, इसलिए वह विपक्षी पार्टी राजद और कांग्रेस को इतना कमजोर कर देना चाहती है कि उसके सहयोग से जदयू पुरानी बारगेनिंग करने लायक नहीं बचे। इसलिए वह इस बार जदयू की सीटों की संख्या को भी कतरने का मन बना चुकी है। यह सबकुछ करना इसलिए बेहद जरूरी है कि 2026 के पूर्वार्द्ध में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। जहां चुनाव जीतना दिल्ली के बाद मोदी सरकार की हिट लिस्ट में है।

समझा जाता है कि एक के बाद एक यानी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी मुश्किल विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरा चुकी भाजपा अब बिहार में भी वही प्रयोग करने जा रही है। आरएसएस और अपनी आनुषंगिक इकाइयों के माध्यम से वह जन जन को साधना चाहती है, ताकि नीतीश कुमार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे और सीटों के बंटवारे में वो कम सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाएं। वहीं, यदि इसमें को अप्रत्याशित बाधा भी आए तो राज्य में हिंदुत्व की लहर इतनी प्रचंड हो जाए कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसी जातिवादी और धार्मिक सोच हवा-हवाई हो जाए।

यही वजह है कि गोपालगंज में बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 5 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव की सियासी नींद उड़ चुकी है। वहीं, प्रयागराज महाकुंभ के बाद भाजपा की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय हवा बनी है, उससे भी ये नेता भीतर ही भीतर परेशान हैं।तेजस्वी यादव और उनके समर्थक तो इस आयोजन को लेकर उटपटांग बयानबाजी भी तेज कर चुके हैं।

वहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के गृह जनपद गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्रीराम जानकी मठ इन दिनों हिंदुत्व व सनातनियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस श्रीराम जानकी मठ में धीरेंद्र शास्त्री ने कथा से पहले हिन्दुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। गुरुवार की देर शाम कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वे यहां अपने लिए थोड़े आए हैं, वे इस देश के हिन्दुओं को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा वे अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिन्दुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं।

उन्होंने कथा के दौरान यहां तक कह दिया कि, वे किसी पार्टी के लिए थोड़े आते हैं। वे किसी के लिए वोट मांगने थोड़े आते हैं। वे तो सिर्फ हिन्दुओं के अलख को जगाने आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने साफ-साफ अंदाज में कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यानी उनके खिलाफ जगह जगह बयान देने वालों के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने दो टूक शब्दों में %सेम टू यू% वाला मुहावरा दुहरा दिया।

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने प्रवचन में हिंदुत्व और हिंदु राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और दो टूक कहा था कि देश में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नहीं बल्कि हिंदुत्व इंटेलिजेंस (एच आई) भी होना चाहिए। तब मीडिया से मुखातिब होते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यहां तक कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा प्रयत्न जारी है। भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना, जैसे दुबई में अलग-अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। उसी तरह भारत में भी सबको रहने का अधिकार है। यह भारत किसी का एक नहीं बल्कि सबका है। इससे उनके श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ी। इस मौके पर ही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा था कि सबके दादा-परदादाओं ने आजादी के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब है जीवन जीने की सही विचार धारा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

आज के युग की तरह अनधिकारी लोग केवल मुतायला करके आर्ष-साहित्य के तत्त्व को नहीं जान सकते थे। जैसे अमूल्य रत्नों को पेटियों में बन्द करके ताले लगा दिये जाते हैं और रखने के स्थान का द्वार भी ऐसा गुप्त और अटपटा बना दिया जाता है कि जिसमें सर्वसाधारण का प्रवेश ही न होने पाए, ठीक इसी भांति जिन तत्त्वों पर हिन्दूराष्ट्र की सार्व-भौमिकता निर्भर थी उन तत्त्वों पर सदा नियन्त्रण रखा जाता था।

जैसे आजकल अमेरिका परमाणुबम के रहस्यों को केवल अपने लिये सुरक्षित रखकर संसार पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता है, अन्यान्य स्वतन्त्र राष्ट्र भी अपनी अपनी खोज का गर्व रखते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं, इसीप्रकार आर्यजाति ने भी अपने वैदिक रहस्यों को सुरक्षित रक्खा था। आज की सुरक्षा का आधार तो केवल गोरी या काली चमड़ी का तारतम्य तथा शासक और दास भेत है, परन्तु हमारी सभ्यता में-- असूयकायाऽनृज वेऽयताय न मा ब्रूया: के अनुसार अनधिकारी और अधिकारी बनने के लिये तत्तत् व्यक्ति की आध्यात्मिक योग्यता ही एकमात्र प्रधान आधार थी। सौ पौराणिक रहस्य की सुरक्षा का अन्यतम प्रयत्न यह विमिश्रण शैली है! इससे ऐरे गरे नत्थू खैरे अनधिकारियों को पुराणों द्वारा वेदों के गहन तत्त्वों तक पहुँचने का अवसर नहीं दिया गया।

इस प्रकार हम पुराणान्तर्वर्ती आर्ष और पारिभाषिक शब्दों, रोचक भयानक और यथार्थ वचनों, समाधि लौकिकी और परकीया नामक त्रिविध भाषाओं, आध्यात्मिकादि बहुविध अर्थों के निरूपण द्वारा पुराणों की शैली और उसकी लोकोत्तर विशेषता को दिखाने के अनन्तर इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं।

क्रमश: ...

चार सौ साल से वीरान पड़ा है आलीशान सतखंडा महल

भूपेंद्र कुमार

शायद सन्नाटा ही इस आलीशान सात मंजिला महल का करीब?चार सौ वर्षों से हमसफर है। महज एक दिन मुगल बादशाह जहांगीर के रहने के लिए बनाए गए इस महल को स्थानीय लोग सतखंडा?महल कहते हैं। अफसोस यह कि जहांगीर यहां कभी नहीं आ पाए, और स्वास्तिक के आकार की यह इमारत आबाद न हो सकी। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित यह महल कई मायनों में इतिहास की अजूबी दास्तान समेटे खामोशी से खड़ा है।

इस ऐतिहासिक कथा का सिरा ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला?(1605-1627) से जुड़ता है। वह चाहते थे कि उनके मित्र और मुगल शासक जहांगीर उनकी भेंट को स्वीकार करें। इसी वजह से दतिया में एक भव्य महल का निर्माण शुरू किया गया।

लेकिन जहांगीर ने विनम्रता से इस न्योते को ठुकरा दिया। दरअसल, जहांगीर जब शहजादे सलीम थे, तब उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने ही मुगल सेनापति अबुल फजल का सिर नरवर में कलम किया था। 440 कमरों और सात तलों वाली इस इमारत को कभी भी रहने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, वीर सिंह ओरछा में रहते थे। उन्होंने जहांगीर के लिए दतिया में छोटे-बड़े 52 महल बनवाए थे। लेकिन सबसे शानदार यही है। कुछ लोग इसे पुराना महल भी कहते हैं। इसे गोविंद महल, गोविंद मंदिर, जहांगीर महल, बीर सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली के वास्तुविद सर एडवर्ड लुटियंस इस इमारत की वास्तुकला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका इस्तेमाल दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को डिजाइन करने में किया। महल की ख्याति सुन 1818 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यहां दरबार लगाया था।

वर्ष 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के साथ यहां आए इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसे बेहद शानदार बताया था। महल के निर्माण में नौ साल लगे और 35 लाख रुपये लागत आई। मथुरा में वीर सिंह को सोने में तोला गया था, उसका इस्तेमाल इसे बनाने में किया गया। गाइड लखनलाल रजक बताते हैं कि आपको इसकी पांच ही मंजिलें नजर आएंगी। दो मंजिलें जमीन के अंदर हैं। जमीन में भी कमरों व सुरंगों का जाल है।?इसे बनाने में लोहे या लकड़ी का?इस्तेमाल नहीं किया गया है। इमारत पत्थर और ईंटों के दम पर खड़ी है। इस महल तक पहुंचने का रास्ता गलियों से होकर गुजरता है। लेकिन एक बार जब आप इसके सामने होते हैं, तो आसपास का परिवेश बेमानी हो जाता है और एक सन्नाटा-सा अंदर तक पसर जाता है।...शायद यही इस महल की नियति है।

ट्रंप का जवाबी शुल्क भारत के लिए मौका

अजित रानाडे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शब्दों के इस्तेमाल में माहिर हैं। अमेरिका के संघीय आयकर विभाग को इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहा जाता है। ट्रंप ने कहा कि वह एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस विभाग बनायेंगे। अपने करदाताओं पर करों का बोझ बढ़ाने के बजाय उन्होंने बाहरियों पर टैक्स लगाने के बारे में सोचा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दुनिया का सबसे खुला हुआ उपभोक्ता बाजार है, जहां हर देश की पहुंच है। पर अमेरिका को निर्यात करने वाले देशों ने अपने यहां दूसरे देशों का प्रवेश बाधित करने के लिए शुल्क की दर काफी ऊंची रखी है। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिकी निर्यात के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे तमाम देशों के उत्पादों पर ऊंचा शुल्क प्रस्तावित किया है। यह 'जैसे को तैसे' की रणनीति है।

ट्रंप के मुताबिक, इससे अमेरिका के राजस्व में भारी वृद्धि होगी और उन देशों को दंड मिलेगा, जो संरक्षणवादी रवैया अपनाते हैं। यह फैसला लेते हुए ट्रंप ने इसका ध्यान नहीं रखा कि डब्ल्यूटीओ का नियम एक ही उत्पाद पर अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग शुल्क लगाने की इजाजत नहीं देता। यह तो एफएमएन-यानी सबसे वरीयता प्राप्त देश वाला नियम है। ट्रंप ने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि उनका फैसला अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी असर डालेगा, क्योंकि इससे कीमत बढ़ेगी और मुद्रास्फीति भी। ट्रंप ने हालांकि कहा है कि अपने नागरिकों को राहत देने के लिए वह आयकर में कटौती करेंगे, लेकिन अमेरिका में भारी राजकोषीय घाटे को देखते हुए यह संभव नहीं लगता।

ट्रंप ने इस पर भी विचार नहीं किया कि अमेरिका की तुलना में भारत जैसे विकासशील देशों को ऊंचे आयात शुल्क दरअसल अपने घरेलू उद्योग

को बचाने के लिए रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनके यहां बिजली, ढांचागत सुविधाओं तथा कर्ज की लागत ज्यादा है, जबकि श्रम उत्पादकता कम है। डब्ल्यूटीओ की यह व्यवस्था, जाहिर है, भारत जैसे विकासशील देशों को अपना घरेलू उद्योग बचाने और विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने के लिए बनायी गयी है। हालांकि यह भी सही है कि जो भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, शुल्कों की ऊंची और रक्षात्मक दीवार बनाये रखना उसे शोभा नहीं देता। ऊंचा आयात शुल्क न प्रतिस्पर्धा के लिए ठीक है, न यह भारतीय उपभोक्ताओं के हित में है, जिन्हें मुफ्त आयात से वंचित रखा जाता है, न यह उन अकुशल उद्योगों के हित में है, जो संरक्षणवादी माहौल में ही फलते-फूलते हैं। ट्रंप के जवाबी शुल्क का प्रस्ताव भारत के लिए अवसर है कि वह कम से कम उन वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करे, जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुल्कों पर यह आपसी सहमति बेशक डब्ल्यूटीओ के नियम के विपरीत होगी, पर ट्रंप के राष्ट्रपति काल में डब्ल्यूटीओ के नियम भी कमोबेश महत्वहीन साबित हो रहे हैं। हालांकि भारत जिस तरह अलग-अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की कोशिश में है, वह भी डब्ल्यूटीओ की घटी साख के बारे में बताता है।

ट्रंप के तेवर भारत के लिए शुल्क सुधार की शुरुआत करने का अवसर होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा शुल्क व्यवस्था न हमारे निर्यात के लिए ठीक है, न यह प्रतिस्पर्धा के अनुकूल है। विदेशी आयात पर सामान्य शुल्क तो 2015 से ही बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे चार से पांच फीसदी तक बढ़ गये हैं, जबकि गैरकृषि उत्पादों में यह वृद्धि औसतन 15 फीसदी है। जिन उत्पादों पर शुल्क एमएफएन शुल्क से 15 फीसदी अधिक थे, उनमें भी एक चौथाई वृद्धि हुई है। 'मेक इन इंडिया' और बाद में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना के लिए आयात शुल्क में लगातार की गयी वृद्धि को उचित ठहराया गया। पर अब आयात शुल्क को 2015 के स्तर से नीचे ले जाने का समय आ गया है। लाजिमी है कि आयात शुल्क को हम आसियान देशों के आयात शुल्क के बराबर ले आयें।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक अमेरिका को हमारा निर्यात 5।6 प्रतिशत बढ़कर 60 अरब डॉलर हो चुका है। अमेरिका के साथ व्यापार में भारत लगभग 45 अरब डॉलर के फायदे में रहता है। अमेरिकी आयात पर भारत सामान्यत: 17 फीसदी शुल्क लगाता है, जबकि भारतीय आयात पर अमेरिकी शुल्क 3।3 प्रतिशत है। भारत और अमेरिका के बीच शुल्कों में अंतर सात से आठ प्रतिशत का है, हालांकि इसमें कृषि उत्पाद शामिल नहीं हैं। अब भारतीय आयातों पर अमेरिका में शुल्क वृद्धि से हमारे इस्पात, एल्यूमीनियम, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को नुकसान होगा। पर फार्मा, पॉलिश किये गये हीरे और पेट्रो उत्पादों के बड़े हिस्से का आयात होता है, इसलिए हम पर नकारात्मक असर कम होगा।

भारत का अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल लेने पर सहमत होना शुल्कों पर हो रही वार्ता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हर्ले डेविडसन मोटरसाइकिल या बार्बन ह्विस्की को शुल्क से छूट देने या इन पर शुल्क कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रवेश बाधित होना हमारे लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। बड़ी अमेरिकी कंपनियों द्वारा संचालित ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स का भारत में होना हमारी प्रतिभा का ही प्रमाण है। इस सिलसिले को बनाये रखना भारत के हित में होगा। अगर इसके लिए आयात शुल्क में कमी करनी पड़े, तो हर्ज नहीं है।

भारत कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में भी सोच सकता है, जिसमें अकूत संभावनायें हैं। भारत से कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का कुल निर्यात 50 अरब डॉलर का है, और जो कुल वैश्विक निर्यात का मात्र 1।5 फीसदी ही है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया का सबसे अधिक पशुधन भारत में है, फलों और सब्जियों का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, और यहां लंबा समुद्रतट भी है। इतनी संभावनाओं के बीच हम दुग्ध उत्पाद, पनीर, मिठाइयों, मांस, पोल्ट्री, मछली, फरूट जूस, ऑर्गेनिक फूड्स आदि के निर्यातक कब बनेंगे? कृषि क्षेत्र में 'छोटे किसानों के हितों' की बात करते हुए आयात और निर्यात पर भारी शुल्क की दीवार बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। जिन कृषि उत्पादों की हम उपेक्षा करते आये हैं। वे अमेरिका के साथ व्यापार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ट्रंप की 'जैसे को तैसा' वाली रणनीति भारत के लिए अवसर है कि हम आयात शुल्क कम करें और निर्यातकों को बड़ा अवसर मुहैया करायें। इसमें हमें थोड़ा नुकसान होगा, पर इसका व्यापक सकारात्मक असर दिखेगा।

आज का इतिहास

1978 वियतनाम, बी-ओ के साथ एक अल्पकालिक कठपुतली राज्य है? मैं इसके शासक के रूप में।
1978 तेल अवीव के उत्तर में एक बस को हाईजैक करने के बाद, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन के सदस्य फतह ने इजरायल पुलिस के साथ गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप 38 नागरिकों और अधिकांश अपराधियों की मौत हो गई।
1978 इजरायली शहर तेल अवीव में आतंकवादी हमले में 45 लोगों की मौत हुई।
1985 मोहम्मद अल-फ़ैद लंदन स्थित डिपार्टमेंट स्टोर कंपनी हैरोड्स को ख़रीदा।
1985 सोवियक संघ के पहले और अंतिम राष्ट्रपति मिखाएल गोर्बाचेव सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बने।
1986 रोम की पारंपरिक नींव के बाद से 1 मिलियन दिन बीत गए।
1990 मैगी ने डेजर्ट इन एलपीजीए गोल्फ इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती।
1991 एमेच्योर पहलवान, जॉन स्मिथ ने कुश्ती चैंपियनशिप जीती और उन्हें एस जेम्स ई सुलिवन पुरस्कार 'से सम्मानित किया गया।
1993 कर्ट ब्राउनिंग ने प्राग में आयोजित पुरुषों की फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप जीती।
1993 जेनेट रेनो की पुष्टि अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में की थी।
1996 तीसरा शतक बनाने के लिए वर्ल्ड कप में मार्क वॉ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 110 रन बनाए।
1997 सैन फ्रांसिस्को के दिग्गज जे.टी. बर्फ एक फ्रैक्चर आंख सॉकेट से ग्रस्त है। पिच से टकराने पर उनकी आंख का सॉकेट टूट गया था।
1998 डेनिश संसदीय चुनाव 1998: प्रधानमंत्री पुल न्यूरुप रासमुसेन फिर से निर्वाचित हुए।
2004 Cercaní कम्प्यूटर पर एक साथ बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने 191 लोगों को प्रशिक्षित किया और मैड्रिड (स्मारक) में 1,800 से अधिक लोगों को घायल कर दिया।
2004 स्पेन की राजधानी मेड्रिड में रेल नेटवर्क पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में 191 लोगों की मौत हुई।

विचारों की एक शृंखला... जो बताएगी कितना बदल गया है यूरोप!

रामचंद्र गुहा

इस साल का 28 फरवरी वह दिन है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपमानित किया गया। साल 1990 में प्रकाशित पत्रिका 'ग्रांटा' में एक शीर्षक था 'न्यू यूरोप!' यह नया विशेषण और विस्मयादिबोधक चिह्न पिछले कई सालों की युगांतकारी घटनाओं की ओर संकेत करते हैं, जिनमें बर्लिन की दीवार का गिरना, पोलैंड में दशकों बाद पहला स्वतंत्र चुनाव और पूर्वी यूरोप में अधिनायकवाद का पतन शामिल है।

1989 की उन घटनाओं का महाद्वीप और विश्व के भविष्य के लिए क्या अर्थ है, इसका आकलन करने के लिए ग्रांटा में यूरोपीय मूल के 15 लेखकों से लेख लिखवाए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं को लेकर कई लेखक खुश भी थे। इनमें पूर्वी जर्मनी के पादरी वर्नर क्रेशेल शामिल थे, जिन्होंने दीवार गिराने वाली 'आजादी और सम्मान' के संघर्ष को सलाम किया। प्रसिद्ध चेक उपन्यासकार इवान क्लिमा का मानना था कि जिन असंतुष्टों ने अधिनायकवाद को समाप्त करने में मदद की थी, उनके पास 'पारस्परिक घरेलू शांति में रहने वाले यूरोप के विचार को साकार करने की शक्ति थी।'

यूरोप में होने वाले बदलावों को सकारात्मक नजरिए से देखने वालों में राजनीतिक सिद्धांतकार इसायाह बर्लिन भी शामिल थे, जो पुराने लेखक होने के साथ अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे। रूस में जन्मे बर्लिन बचपन में ही परिवार के साथ ब्रिटेन चले गए थे। उन्होंने 1989 की घटनाओं में पुराने साम्यवाद द्वारा दमन किए गए बुद्धिजीवियों की उदार परंपराओं का पुनरुत्थान देखा। उन्होंने लिखा, रूसी महान हैं। उनके पास अपार रचनात्मक शक्तियां हैं और एक बार मुक्त होने के बाद यह कहना मुश्किल हो सकता है कि वे दुनिया को क्या दे सकते हैं। एक नए प्रकार की बर्बरता हमेशा संभव है, लेकिन मुझे वर्तमान में इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है कि बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है और दासता को खत्म किया जा सकता है, जिन पर मनुष्य सही मायने में गर्व कर सकता है।

अन्य लेखकों ने भी पूर्वी यूरोप में सोवियत के कठपुतली शासन के पतन का स्वागत किया, लेकिन वे भविष्य को लेकर बहुत आशावादी नहीं थे। चेक गणराज्य में जन्मे और कई सालों तक कनाडा में रहे लेखक जोसफ स्कोवोरेस्की ने लिखा, यूरोप में अधिनायकवादियों के दिन गिने-चुने रह गए हैं। अन्य जगहों पर ऐसा लगता है कि वे नहीं रहे, कुछ जगहों पर तो वे अभी-अभी शुरू हुए हैं। आलोचक जॉर्ज स्टीनर ने टिप्पणी की, हम हर जगह, राष्ट्रवाद, बढ़ती जातीय घृणा के बीच एक अंधी दौड़ देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा यूरोप की अनेदखी के बाद भी यूरोप अपने दम पर खड़ा है।

पूर्वी यूरोप में जो कुछ भी हुआ, वह पोलिश, चेक, मैग्यार और जर्मन द्वारा दबाई गई राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी, जो सोवियत शासन का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ योगदानकर्ताओं ने तो इन छोटे यूरोपीय राष्ट्रों के उदय का जश्न मनाया। ग्रांटा में लिखे लेख में आंद्रेई सिन्यावस्की ने चेतावनी दी कि राष्ट्रवाद के

प्रतिक्रियावादी और मुक्तिदायी परिणाम भी हो सकते हैं। इसकी सबसे अधिक संभावना रूस में थी। वह भले ही साम्राज्य से वंचित था, लेकिन अपने गौरव से नहीं। उन्होंने लिखा, राष्ट्रवाद स्वयं में किसी राष्ट्र के लिए कोई गंभीर खतरा तब तक नहीं हो सकता, जब तक वह बिना किसी ठोस आधार के अपने 'शत्रु' न बनाना शुरू कर दे। उन्होंने आगे कहा, अब रूसी राष्ट्रवादियों ने 'रूसोफोबिया' को जन्म दिया है, जो 'बुर्जुआ घुसपैठ' के लेनिनवादी-स्टालिनवादी विचार का संशोधित रूप है। रूसोफोबिया स्टालिनवाद का वह भयानक रूप है, जो 'लोगों का दुश्मन' और 'वैचारिक तोड़-फोड़ करने वाला' है।

बर्लिन और सिन्यावस्की की टिप्पणियां छपने के 35 साल बाद भी उन्हें एक साथ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि एक के आशावाद और दूसरे के संदेह के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। इसका कारण दोनों की अलग सोच हो सकती है। उन्हें पता था कि रूसी राष्ट्रवाद में किस तरह विदेशी-द्वेष और अंधराष्ट्रवादी प्रवृत्तियां थीं। कम से कम रूस के मामले में तो सिन्यावस्की, बर्लिन से ज्यादा सटीक साबित हुए हैं। दशकों से सत्ता पर काबिज व्लादिमीर पुतिन ने पहले अपने लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, फिर उन देशों के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद आजाद हुए थे। रूस की यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा यूक्रेन पर हमले में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, हालांकि पुतिन की नजर कुछ छोटे यूरोपीय देशों पर भी है।

पिछले कुछ हफ्तों में हुए घटनाक्रम बताते हैं कि ग्रांटा में योगदान करने वालों में जॉर्ज स्टीनर दूरदर्शी थे। उनका मानना था कि समय के साथ अमेरिका यूरोप के प्रति उदासीन हो जाएगा। हालांकि यह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुतिन की प्रशंसा से पहले से ही जगजाहिर था, लेकिन कम ही लोगों ने सोचा था कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ इतने आक्रामक हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा वोलोदिमीर जेलेंस्की का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने का रूसी राजनेताओं और प्रचारकों ने स्वागत किया है। ट्रंप इसका अनुमान शायद ही लगा पाए होंगे कि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी इतनी जल्दी उस संकटग्रस्त देश की मदद के लिए आगे आ जाएंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस तीखी नोकझोंक के लाइव प्रसारण के कुछ ही घंटों के भीतर यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की- 'यूक्रेन यूरोप है! हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, ताकि वह रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। आज यह स्पष्ट हो गया है कि स्वतंत्र विश्व को एक नए नेता की जरूरत है। यह हमारे ऊपर है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें।'

मौजूदा कार्यभार संभालने से पहले कलास एस्टोनिया की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। यह छोटा, लेकिन आत्मसम्मान वाला बाल्टिक गणराज्य है। यह कभी सोवियत शासन के अधीन था। पुतिन अब भी इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। हालांकि कलास की विद्रोही पोस्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा यूक्रेन के प्रति दिखाई गई एकजुटता थी। उन्होंने जेलेंस्की को अपने आधिकारिक निवास पर आमंत्रित कर उन्हें वह सम्मान देने की पेशकश की, जो उन्हें व्हाइट हाउस में नहीं दिया गया था। इसके बाद यूरोपीय नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की गई।

इन सबके बावजूद यूरोपीय राजनेताओं को यह पता है कि उनके पास यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए सैन्य शक्ति का अभाव है। लेकिन उन्हें अब भी इस बात की उम्मीद है कि ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को अचानक वापस लेने के अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेंगे। शायद वह अमेरिकी कंपनियों को यूक्रेन के बहुमूल्य खनिज संसाधनों का दोहन कर उससे लाभ कमाने का लालच भी दे सकते हैं।

हालांकि मैं इस कॉलम को उस संगोष्ठी की एक टिप्पणी के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो स्टीनर और सिन्यावस्की की टिप्पणियों से भी अधिक दूरदर्शी थी। यह टिप्पणी पूर्वी जर्मन असंतुष्ट लेखक जुरेक बेकर की थी, जिसमें कहा गया था, पश्चिमी समाज का कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। अगर कोई मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो वह है उपभोक्तावाद।

21 मिलियन डॉलर के झूठ का खेल

योगेन्द्र यादव

कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। नहीं होते होंगे, लेकिन पंख जरूर होते हैं। यकीन न हो तो देख लीजिए कि पिछले दो सप्ताह से देश और दुनिया में 21 मिलियन डॉलर वाला झूठ कितनी तेजी से घूमा। चाहें तो इस बहाने यह भी समझ लीजिए कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का यह गोरखधंधा चलता कैसे है। बात शुरू हुई अमरीका से। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प ने धन्नासेठ एलन मस्क को जिम्मेदारी दी कि वह अमरीकी सरकार के खर्चे में कटौती करें। मस्क के दफ्तर ने सबसे पहले अमरीका के विदेश मंत्रालय की मार्फत दुनिया में सहायता बांटने वाली संस्था यू.एस. एड को बंद करने की घोषणा की। फिजूलखर्ची के सबूत के तौर पर एक लिस्ट जारी की, जिसमें भारत में मतदान बढ़ौतरी के लिए दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर (आज लगभग 170 करोड़ रुपए) की ग्रांट रद्द करने का जिक्र था। पिछली सरकार का मखौल उड़ाते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी इसी उदाहरण को दोहराया और पूछा कि आखिर राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार भारत के चुनाव में 'किसी और' को जिताना चाहती थी? बस अब क्या था। भारत में इसे यूं पेश किया गया कि अमरीकी सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव में दखलअंदाजी करने के लिए पैसा दिया था। आरोप संगीन था। लेकिन किसी को जांच करने की फुर्सत नहीं थी। यह पूछने की भी नहीं, कि आखिर मोदी सरकार की नाक के नीचे अमरीकी सरकार भारत में मोदी को हराने के लिए पैसे भेज कैसे सकती थी। सरकार सो रही थी क्या? आनन-फानन में सभी लोग पिल पड़े। लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल और आई.टी. सैल के अमित मालवीय समेत पूरा सरकारी तंत्र, दरबारी मीडिया और भक्त मंडली टूट पड़ी। कांग्रेस और विपक्षी दलों पर उंगलियां उठाई गईं। यही नही, अमरीकी पैसा किस-किस पत्रकार और आंदोलनजीवी के पास पहुंचा होगा, उसकी सूची और फोटो भी चल निकली। लेकिन हाय, जल्द ही सारा गुड़ गोबर हो गया। देश के एक अखबार 'इंडियन एक्सप्रैस' ने इस खबर की जांच करने की जहमत उठाई और पाया कि सारी कहानी कपोल-कल्पित थी। यानी कि यू.एस. एड द्वारा भारत को ऐसी कोई 21 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी ही नहीं गई थी। अगर इस राशि की कोई ग्रांट थी तो वह बंगलादेश में चुनावी जागरूकता के लिए 'नागोरिक प्रोजैक्ट' के तहत दी गई थी। शायद एलन मस्क के दफ्तर ने बंगलादेश और भारत में घालमेल कर दिया होगा। अगले दिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसमें यू.एस. एड की भारत में हुई सारी फंडिंग का ब्यौरा है। उसमें चुनाव से जुड़ी किसी ग्रांट का जिक्र नहीं है। यही नहीं, पता लगा कि जिस यू.एस. एड को देश के लिए खतरा बताया जा रहा था, उससे भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों का घनिष्ठ रिश्ता है, ज्वायंट प्रोजैक्ट चल रहे हैं, बैठकें हो रहीं हैं। स्मृति ईरानी इसी यू.एस. एड की एम्बैसेडर रह चुकी हैं। भाजपा नेताओं के यू..एस. एड के प्रतिनिधियों के साथ दर्जनों फोटो निकल आए। कायदे से तो झूठ का गुब्बारा फटने के बाद इसका प्रचार करने वालों को माफी मांगनी चाहिए थी। कम से कम यह फेक न्यूज बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन माफी मांगने की बजाय आई.टी. सैल अब 'इंडियन एक्सप्रैस' के पीछे पड़ा। भंडाफोड़ होने के बाद भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि अमरीका से आई खबर चिंताजनक है, इसकी जांच की जाएगी।

विश्व का खलनायक बन रहे ट्रम्प!

अवधेश कुमार

अमरीका का राष्ट्रपति पद संभालने के साथ डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दिए वक्तव्यों, निर्णयों तथा विदेशी नेताओं के साथ व्यवहार से निस्संदेह, अमरीकी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर आशंकाएं पैदा हुई हैं। यह तो अनुमान था कि वे जो बाइडेन की नीतियों में व्यापक बदलाव लाएंगे, लेकिन इस सीमा तक जाएंगे इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। पश्चिम एशिया की समस्या पर यह वक्तव्य देकर उन्होंने हलचल मचा दी कि गाजा पट्टी पर कब्जा कर उसका पुनर्निर्माण करेंगे एवं नए सिरे से बसाएंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध पर उनकी नीति उलट गई है। वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधा संपर्क कर बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के बीच समझौता तय हो गया है। यूरोपीय देशों को वे यूक्रेन को सैन्य व अन्य सहयोग पर लगातार खरी-खरी सुना रहे हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ ह्वाइट हाऊस की संयुक्त पत्रकार वार्ता में उनकी बहस हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तो ह्वाइट हाऊस से निकाला गया। साफ था कि ट्रम्प उन्हें युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए डांट रहे हैं कि आप तृतीय विश्व युद्ध कराने की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह का व्यवहार किसी राष्ट्र प्रमुख का कभी देखा नहीं गया। अमरीका सहित विश्व भर में ट्रम्प विरोधियों की बड़ी संख्या है तथा विश्व को अपने किस्म की व्यवस्था देने की बौद्धिक, वित्तीय, व्यावसायिक,

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक आदि व्यवस्थाएं देने में लगे राज्य, गैर राज्य शक्तियां-संगठन-समूह आदि ट्रम्प को समाज एवं विश्व का खलनायक बनाने की होड़ में लगे हैं। सामान्य तौर पर लगता है कि कोई नासमझ या सिरफिरा व्यक्ति अमरीकी राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गया है। व्यवहार ऐसा है जो होना नहीं चाहिए। क्या यही सच है? न भूलिए कि ट्रम्प अमरीकी राष्ट्रपति हैं और अमरीका की शिक्षित जनता ने उन्हें सीधे निर्वाचित किया है। ऐसा व्यक्ति न सिरफिरा हो सकता है और न बिना सोचे-समझे या गैर योजना से कुछ करेगा। इसलिए मान लीजिए कि ट्रम्प सुनियोजित तरीके से अपनी रणनीति के तहत बढ़ रहे हैं और उनके निश्चित लक्ष्य हैं।

संसद के संयुक्त संबोधन में उन्होंने अमरीका और पूरे विश्व के लिए अपनी कार्ययोजना को रख दिया है। यह बात अलग है कि वर्तमान विश्व की संरचनाओं, जटिलताओं और उथल-पुथल की स्थिति में ट्रम्प के लिए इच्छित लक्ष्य पाना कठिन है। इसे वे और उनके सलाहकार भी समझ रहे हैं। 2020 में सत्ता से जाने के बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की थीं और पिछले करीब डेढ़ वर्ष से उन्होंने चुनाव अभियान में जनता के समक्ष सारी बातें रखीं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या विश्व भर में शक्तिशाली अतिवादी इकोसिस्टम और बनाए गए नैरेटिव से बाहर निकलकर उनके व्यवहार से आए कुछ त्वरित परिणामों पर दृष्टि डालिए। क्या इमैनुएल मैक्रों और जेलेंस्की के साथ लाइव विवाद के बाद इस इकोसिस्टम द्वारा जो नैरेटिव बनाकर डर और आशंकाएं पैदा की जा रही हैं उसकी परिणति भी वैसे ही सामने आई है?

ट्रम्प ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी सहायता रोक दी। यानी यह अगला अतिवादी कदम था जिससे पता चलता था कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसे करने की उनकी तैयारी है। पहला परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय देशों ने लंदन में बैठे तथा यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए एक रूप-रेखा बनाने पर सहमति व्यक्त की। यद्यपि फ्रांस की ओर से डोनाल्ड ट्रम्प के विरुद्ध बयान आ रहे हैं किंतु उस बैठक से ऐसा वक्तव्य नहीं आया।जब ट्रम्प ने कहा कि वह हमास और फिलिस्तीनियों को निकाल बाहर करेंगे तथा गाजा पर कब्जा कर इसका निर्माण कर आगे बस्ती बसाएंगे तो कई देशों ने विरोध किया था। ट्रम्प के प्रभाव में ही हमास ने युद्ध विराम समझौता कर इसराइली बंधकों को रिहा करना शुरू किया था।

ट्रम्प का रुख अभी भी वही है। इस तरह अभी तक ट्रम्प के कदमों से दुनिया में हलचल तो मची किंतु कोई विपरीत परिणाम नहीं आया है। युद्ध रोकना है तो पुतिन को विश्वास में लेकर बात करनी होगी। ट्रम्प रक्षा नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति से संबंधित सभी प्रमुख लोगों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सहमति और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही वह बयान देते हैं या कदम उठाते हैं। अमरीका विश्व में 1.7 खरब डालर के सर्वाधिक व्यापार घाटे में है। उनके टैरिफ के प्रत्युत्तर में कनाडा, मैक्सिको, चीन आदि ने भी इस तरह जवाबी टैरिफ लागू किया है। इससे डर इसलिए पैदा हुआ है कि अभी तक की व्यवस्था में उथल-पुथल जैसा है। ट्रम्प द्वारा लगातार भारत का नाम लेने के बावजूद भारतीय सामग्रियों पर प्रतिक्रियात्मक टैरिफ नहीं लगा है। हां, 2 अप्रैल से वैश्विक व्यापार नीति के तहत समानुपातिक शुल्क में भारत भी आएगा। भारत का रुख संतुलित है, प्रतिक्रियात्मक कदमों की घोषणा नहीं की गई क्योंकि अमरीका सर्वाधिक व्यापारिक लाभ देने वाला सांझेदार है।

बदले-बदले से 'सरदार' नजर आते हैं

राकेश सैन

हिन्दी का एक बहुत मशहूर शेयर है ...
बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं,
अपने ही संगी के साथी नहीं अब,
अपनों से अब बेजार नजर आते हैं।

इस शेयर में अगर 'सरकार' की जगह 'सरदार' लिख दिया जाए तो यह पंक्तियां पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पर बिल्कुल स्टीक बैठती हैं। कुछ दिन पहले तक अपने चुटकलों से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले भगवंत मान अब उत्तर प्रदेश के योगी के अंदाज में दिखने लगे हैं। नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दिन में हड़ताली राजस्व अधिकारियों को सीधा-सीधा धमकाते हैं कि 'आपको छुट्टी मुबारक' और शाम होते-होते उन्हें निलम्बित कर देते हैं। और तो और किसान नेताओं को यहां तक कहने लगे हैं कि 'बहुत हो चुका अब आपकी ब्लैकमेलिंग और नहीं चलेगी। आप लोगों ने पंजाब को धरना प्रदेश बना कर रख दिया है।' पंजाब में इन दिनों मुख्यमंत्री के व्यवहार में आए बदलाव के कारण खोजे जा रहे हैं।

वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई पराजय के बाद पंजाब का नेतृत्व दबाव में है और कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि राज्य में 'आप' की क्रान्तिकारी सरकार अपना आधे से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुकी है परन्तु उपलब्धि के नाम पर सरकार के हाथ खाली-खाली से लगते हैं। क्रान्ति अब भ्रान्ति लगने लगी है। पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की छायाप्रति ही रही है। पंजाब में भी दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर आम आदमी क्लीनिक खोले गए, मनीष सिसोदिया के आदर्श स्कूलों की कॉपी करते हुए स्कूल आफ एमिनेंस खोले गए। पंजाब के मंत्री दिल्ली वालों की तरह

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते नहीं अघाते परन्तु दिल्ली के विकास मॉडल के धड़ाम होने के बाद पंजाब का नेतृत्व भी सन्न है। आम आदमी पार्टी की दृष्टि से पंजाब में तो स्थितियां और भी विकराल हैं क्योंकि यहां उसकी सरकार के कार्यकाल में नशा अपनी तमाम सीमाएं तोड़ता दिख रहा है, जबकि पार्टी नशामुक्ति के हिमालयी वायदे करके सत्ता में आई थी। पर आज राज्य में आए दिन कहीं न कहीं नशे की ओवरडोज मौत होने की खबरें मिलती रहती हैं। कुछ जगह पर तो आठ-दस साल के बच्चों के भी नशे करने की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। राज्य में आटे की तरह चिट्टा (हेरोइन) बिक रहा है। नशा महिषासुर राक्षस बन चुका है जिसको जितना मारो उसके रक्त की हर बून्द से नए-नए महिषासुर पैदा हो रहे हैं। पुलिस आए दिन भारी मात्रा में नशा पकडऩे का दावा करती है परन्तु इसके बावजूद पंचनद की धरती पर नशे का छठा दरिया बहता दिखाई देता है। राज्य का सरकारी कर्ज निरंतर बढ़ रहा है तो महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का चुनावी वायदा विपक्षी दल भूलने नहीं दे रहे।

कहते हैं कि एक बार मुल्ला जी ने नदी में बहते हुए रीछ को कम्बल समझ कर पकड़ लिया, पर कुछ ही देर बाद हालत यह हो गई कि मीयां जी तो कम्बल को छोडऩा चाहें पर अब कम्बल मीयां जी को ना छोड़े। यही हालत किसान संगठनों को लेकर भगवंत मान सरकार की होती दिख रही है। दिल्ली में चले किसान आन्दोलन के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलनकारी किसानों को केवल समर्थन ही नहीं दिया बल्कि लंगर-पानी तक पहुंचाने का काम भी किया। समय बदला, अब वही किसान संगठन आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। साल पहले किसानों के नए आंदोलन के तहत दिल्ली कूच करते हुए हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारियों को पंजाब-हरियाणा की सीमा शम्भू बार्डर पर ही रोक दिया था। आन्दोलनकारी किसान तब से वहां पक्का मोर्चा लगाए बैठे हैं। यह आंदोलन अब राज्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। पंजाब की औद्योगिक नगरियां अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना इसी मार्ग से दिल्ली के साथ जुड़ी हैं परन्तु रास्ता बंद होन के कारण न तो कारखानों को कच्चा माल आसानी से सप्लाई हो रहा है और न ही तैयार माल ठिकानों पर पहुंचाया जा सकता है। वैकल्पि मार्ग अपनाने से माल की लागत बढ़ रही है जिससे पंजाब के उद्योगपति पिछड़ रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए आम लोगों को भी गांवों के कच्चे मार्गों से हो कर गुजरना पड़ता है। इससे पंजाब का उद्योग चरमराता जा रहा है, मुख्यमंत्री कई बार देश के बड़े धनपतियों से मिल कर राज्य में नये निवेश का आमंत्रण दे चुके हैं परन्तु जब पहले से स्थापित उद्योग किसान आंदोलनकारियों के कारण त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हों तो भला नया उद्योग कैसे राज्य में आए। पंजाब के उद्योगपति व व्यवसाई कई बार मुख्यमंत्री से भेंट कर इसका स्थाई हल निकालने की मांग कर चुके हैं पर कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में सरदार जी का बदलना समझ आता है।

कुछ विश्लेषक सरदार जी के बदलाव के पीछे पार्टी की आंतरिक राजनीतिक को भी कारण मान रहे हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में कमरतोड़ पराजय के बाद राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अपनी सम्भावनाएं खोज रहे हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के देहांत के बाद वहां रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है। इससे राज्य में इस चर्चा को बल मिला है कि खुद अरविंद केजरीवाल यहां से राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं। भगवंत मान शायद अधिक अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा व लोकसभा की टिकटें बांटने वाले केजरीवाल पंजाब में केवल सांसद बनने के लिए नहीं आरहे, वे कुछ और चाहते हैं। अगर सरदार जी की सरकार यूं ही ढचक-ढचक शैली में चलती रही तो उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। शायद यही कारण है कि भगवंत मान आज 'कमेडियन' से 'कर्मयोगी' बनने की कोशिश में सख्ती दिखा रहे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ...

देख उनकी सादगी पर मिट गए थे कभी,
अब पैंतरे बदलते सरकार नजर आते हैं।
बदले-बदले से 'सरदार' नजर आते हैं।

मणिपुर: सड़कों पर आवागमन शुरू होते ही हिंसा और तनाव

प्रभाकर मणि तिवारी

करीब 22 महीने से जातीय हिंसा की चपेट में रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शनिवार को मुक्त आवागमन की शुरुआत में ही कुकी इलाकों में तमाम संगठनों ने वाहनों की आवाजाही रोकने का प्रयास किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई लोग घायल हो गए। इससे कुकी-बहुल इलाको में नए सिरे से तनाव फैल गया है। दूसरी ओर, लूटे गए सरकारी हथियारों को लौटाने की तारीख खत्म होने के बाद सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। राज्यपाल ने इन हथियारों को लौटाने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी थी। वह समय सीमा छह मार्च को ही पूरी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते सप्ताह दिल्ली में मणिपुर की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई थी। उसमें आठ मार्च से तमाम सड़कों को आवाजाही के लिए खोलने का फैसला किया गया था। जातीय हिंसा के दौर में मैतेई और कुकी संगठनों ने अपने-अपने प्रभाव वाले इलाके में सड़कों पर बैरिकेड लगा कर वाहनों और आम लोगों की आवाजाही रोक दी थी। कुकी संगठनों ने पहले ही कह दिया था कि अलग प्रशासन नहीं मिलने की स्थिति में वो अपने इलाके में सड़कों को आवाजाही के लिए नहीं खोलने देंगे। तमाम कुकी संगठन हिंसा शुरू होने के बाद से ही अपने इलाके के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि मैतेई समुदाय के साथ बढ़ी कड़वाहट के बाद अब उनके साथ रहना संभव नहीं होगा। मणिपुर में बीते महीने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद शनिवार को सुबह कुछ प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी। लेकिन खासकर कुकी-बहुल इलाकों में उनको आम लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य में ज्यादातर प्रमुख सड़कों पर सरकारी बसों की आवाजाही लगभग ठप थी। शनिवार को सड़कें खुलने के बाद भारी सुरक्षा के सात सरकारी बसों का संचालन शुरू किया गया। हालांकि उन बसों में यात्री नहीं के बराबर ही थे। इंफाल से कांग्पोक्पी होकर सेनापति जाने वाली सरकारी बस को बीएसएफ के काफिले के साथ रवाना किया गया था। लेकिन कांग्पोक्पी जिले की सीमा पर कुकी महिलाओं के एक गुट ने सड़क जाम कर दिया था। उसे हटाने के लिए बीएसएफ के जवानो को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद दोनों जिलो की सीमा पर भारी तनाव पैदा हो गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इंफाल से चूड़ाचांदपुर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा भी 12 मार्च से शुरू हो जाएगी। मणिपुर के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इंफाल से कांग्पोक्पी होकर सेनापति और इंफाल से विष्णुपुर होकर चूड़ाचांदपुर तक जाने वाली सड़क बसों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। उन दोनों सड़कों पर थोडी-थोडी दूर पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही बसों के साथ भी सुरक्षाबलों के वाहन तैनात हैं। इस बीच- राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील पर दो सप्ताह की समयसीमा के भीतर एक हजार से ज्यादा सरकारी हथियारों को जमा करा दिया गया है। मार्च, 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद सरकारी शस्त्रागारों और थानों से करीब छह हजार हथियार लूट लिए गए थे। इनको लूटने वालो में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के उग्रवादी संगठन शामिल थे। वैसे, सरकारी हथियार लौटाने की अपील कोई पहली बार नहीं की गई है। इससे पहले जून, 2023 में राज्य में जगह-जगह ड्राप बाक्स रखे गए थे। उन पर लिखा था कि कृपया लूटे गए हथियारों को यहां जमा कर दें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी भरोसा दिया गया था। लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हो सका था। राज्य में करीब एक महीने से राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद सवाल उठ रहा है कि क्या इससे मणिपुर में शांति लौटेगी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुकी संगठन अपने रुख पर अड़े हैं।

काशी विश्वनाथ के अनसुने रहस्य

बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियों 'वरुणा' और 'असि' के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम 'वाराणसी' पड़ा। आओ जानते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के 10 अनसुने रहस्य।

त्रिशुल की नोक कर बसी है काशी

पुरी में जगन्नाथ है तो काशी में विश्वनाथ। भगवान शिव के त्रिशुल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी।

भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी

भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यन्त प्रिय है इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है।

विष्णु की तपोभूमि

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहां एक पुष्कर्णी का निर्माण किया और लगभग पचास हजार वर्षों तक वे यहां घोर तपस्या करते रहे।

सदाशिव ने की उत्पत्ति काशी की

शिवपुराण अनुसार उस कालरूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ 'शिवलोक' नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को 'काशी' कहते हैं। यहां शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहां पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं।

ब्रह्मा विष्णु और महेष की उत्पत्ति

कहते हैं कि यहीं पर सदाशिव से पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, रुद्र और महेष की उत्पत्ति हुई।

काशी में मिलता है मोक्ष

ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहां काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बीताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवथा की गई है। यह शहर सप्तमोक्षदायिनी नगरी में एक है।

उत्तरकाशी भी काशी

उत्तरकाशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तरकाशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तरकाशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तरकाशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु-संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। महाभारत के अनुसार उत्तरकाशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहां घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तरकाशी और भागीरथी, जाह्नवी व भीलगंगा के बारे में वर्णन है।

ज्योतिर्लिंग

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। ह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है इसीलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक 'तीर्थ चिंतामणि' में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही शिवलिंग है।

विष्णु की पुरी

पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे, वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां 'बिंधुमाधव' के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णुजी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई।

धनुषाकारी है यह नगरी

पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है जो पाप-नाशिनी है।

पूजाघर में रखी गरुड़ घंटी के राज

मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। मंदिर या घर के पूजाघर में आपने देखा होगा गरुड़ घंटी को। आओ जानते हैं इस घंटी के राज और पूजाघर में रखने के 5 फायदे।

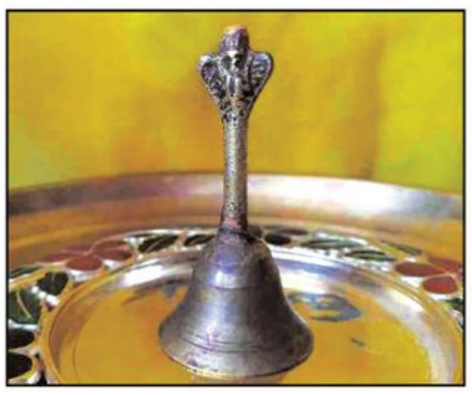

- हिंदू धर्म अनुसार सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है ।इसीलिए घंटी रूप में ध्वनि को मंदिर या पूजाघर में रखा जाता है।
- जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है।
- घटी के रूप में सृष्टि में निरंतर विद्यमा नाद ओंकार या की तरह है जो हमें यह मूल तत्व की याद दिलाता है।
- घंटियां 4 प्रकार की होती हैं :- 1.गरूड़ घंटी, 2. द्वार घंटी, 3 हाथ घंटी और 4.घंटा।
- गरूड़ घंटी छोटी-सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है।
- द्वार घंटी द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है।
- हाथ घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोककर बजाते हैं।
- घंटा बहुत बड़ा होता है। कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर तक चली जाती है।
- भगवान गुरुढ़ के नाम पर है गुरुढ़ घंटी जिस का मुख गुरुण के समान ही होता है। भगवान गरुड़ को विष्णु का वाहन और द्वारपाल माना जाता है। अधिकतर मंदिरों में मंदिर के बाहर आपको द्वार पर गरुड़ भगवान की मूर्ति मिलेगी। दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर इसे देखा जा सकता है।
- घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानि आवाज प्रकट होगी

फायदे

- घंटी विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ऐसा कहते हैं कि घंटी बजाने से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है। इस कंपन के वायुमंडल में फैलने से जीवाणु, विषाणु इस तरह के सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है।
- घर के पूजाघर या मंदिर में प्रात: और संध्या को ही आरती करते वक्त घंटी बजाने का नियम है। वह भी लयपूर्ण। इससे हमारा मन शांत होकर तनाव हट जाता है।
- जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां से नकारात्मक शक्तियां हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वारा खुलते हैं। इससे सभी तरह के वास्तुदोष भी दूर हो जाते हैं।
- स्कंद पुराण के अनुसार घंटी बजाने से मानव के सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
- यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है।

कुल देवी या देवता को 4 उपाय से मनाएं और संकटों से मुक्ति पाएं

भारत में कई समाज या जाति के कुलदेवी और देवता होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपाने कुलदेवी और कुल देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया है। संभवत: इसी के कारण वे घोर संकट में घिरे हुए हैं। यदि ऐसा है तो 4 उपाय करें और संकटों से मुक्ति पाएं।

- जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है सौ सुनार की एक लोहार की। बिना कुलदेवी कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या कोई नाम, यश आगे बढ़ नहीं सकता। अत: कुल देवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। स्थान का नाम भी नहीं मालूम हो तो तो हे माता कुलदेवी और कुलदेवता आपकी सदा विजयी हो। दुर्गा माता की जय, भैरू महाराज की जय।
- एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। जिसे यह नहीं याद है वे भैरू महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोज चढ़ाएं और पूजा करें।
- कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबूत नींबू लें और उसको अपने उपर से 21 बार वार कर उसे दो भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांग कर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान-दक्षिणा दें।
- कुलदेवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें की टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। कुलदेवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी-देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह-शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए।

हिन्दू धर्म में क्यों महत्व है लाल रंग का

वैज्ञानिकों के अनुसार रंग तो मूलत: पांच ही होते हैं- कला, सफेद, लाल, नीला और पीला। काले और सफेद को रंग मानना हमारी मजबूरी है जबकि यह कोई रंग नहीं है। इस तरह तीन ही प्रमुख रंग बच जाते हैं- लाल, पीला और नीला। आपने आग जलते हुए देखी होगी- उसमें यह तीन ही रंग दिखाई देते हैं। हिन्दू धर्म में इन तीनों ही रंगों को महत्व है, क्योंकि इन्हीं में हरा, केसरिया, नारंगी आदि रंग समाए हुए हैं। लाल रंग के अंतर्गत सिंदुरिया, केसरिया या भगवा का उपयोग भी कर सकते हैं।

- हिन्दू धर्म अनुसार लाल रंग उत्साह, सौभाग्य, उमंग, साहस और नवजीवन का प्रतीक है। लाल रंग उग्रता का भी प्रतीक है।
- यह रंग अग्नि, रक्त और मंगल ग्रह का रंग भी है।
- हिन्दू धर्म में विवाहित महिला लाल रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनती है।
- प्रकृति में लाल रंग या उसके ही रंग समूह के फूल अधिक पाए जाते हैं।
- लाल रंग माता लक्ष्मी को पसंद है। मां लक्ष्मी लाल वस्त्र पहनती हैं और लाल रंग के कमल पर शोभायमान रहती हैं।
- रामभक्त हनुमान को भी लाल व सिन्दूरी रंग प्रिय हैं इसलिए भक्तगण उन्हें सिन्दूर अर्पित करते हैं।
- मां दुर्गा के मंदिरों में आपको लाल रंग की ही अधिकता दिखाई देगी।
- लाल के साथ भगवा या केसरिया सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी है।
- यह रंग चिरंतन, सनातनी, पुनर्जन्म की धारणाओं को बताने वाला रंग है।
- विवाह के समय दुल्हन लाल रंग की साड़ी ही पहनती है और दूल्हा भी लाल या केसरी रंग की पगड़ी ही धारण करता है, जो उसके आने वाले जीवन की खुशहाली से जुड़ी है।
- केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। शिवाजी की सेना का ध्वज, राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग केसरिया ही था। केसरिया या भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है।
- सनातन धर्म में केसरिया रंग उन साधु-संन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है, जो मुमुक्षु होकर मोक्ष के मार्ग पर चलने लिए कृतसंकल्प होते हैं। ऐसे संन्यासी खुद और अपने परिवारों के सदस्यों का पिंडदान करके सभी तरह की मोह-माया त्यागकर आश्रम में रहते हैं। भगवा वस्त्र को संयम, संकल्प और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक माना गया है।

तुंगविद्या की वीणा की धुन पर नाचते थे श्रीकृष्ण

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्रीजी राधारानी की 8 सखियां थीं। अष्टसखियों के नाम हैं- 1.ललिता, 2.विशाखा, 3.चित्रा, 4. इंदुलेखा, 5.चंपकलता, 6.रंगदेवी, 7.तुंगविद्या और 8.सुदेवी। राधारानी की इन आठ सखियों को ही ''अष्टसखी'' कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्टसखियों का मंदिर भी स्थित है। आओ इस बार जानते हैं तुंगविद्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

- सखी तुंगविद्या नृत्य तथा गायन करके श्रीराधा और कृष्ण का मनोरंजन करती हैं।
- इन्हें माता पार्वती गौरी मां का अवतार माना जाता है।
- तुंगविद्या सखी 18 वेद विद्याओं में पारंगत है।
- ये वीणा बजाना भी जानती हैं और नाट्यशास्त्र एवं रसशास्त्र में भी कुशल है।
- इनकी माता का नाम मेघा, पिता का नाम पुष्कर और पति का नाम बालिश है। कुछ जगहों पर इनके पिता का नाम अंगद एवं माता का नाम ब्रह्मकर्णी बताया जाता है।
- कहते हैं कि श्रीकृष्ण तुंगविद्या की विणा पर नाचते थे।
- बरसाना से दक्षिण दिशा में छह किलोमीटर दूर सखी तुंग विद्या का गांव डभाला है। वहीं बरसाना से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित राकोली गांव रंगदेवी सखी का गांव है।
- पहाड़ी पर इनका मंदिर है। तुंगविद्या सखी पीले रंग के परिधान धारण कर भक्तों को दर्शन देती हैं।
- इनका जन्म भाद्रपद शुक्लपक्ष पंचमी को हुआ था।
- राधाजी से पांच दिन छोटी हैं रंगदेवी और तीन दिन बढ़ी है तुंग विद्या।

चरणामृत सेवन के चमत्कारिक फायदे

हिन्दू धर्म में पंचामृत या चरणामृत के साथ तुलसी का सेवन जरूरी है। हर मंदिर में आपको चरणामृत तो मिलेगा पर पंचामृत कम ही मिलेगा। पंचामृत किसी तीज त्योहार पर बनाया जाता है। हालांकि कुछ मंदिरों में प्रतिदिन ही पंचामृत का प्रसाद बंटता है। आओ जानते हैं कि क्या है चरणामृत सेवन के लाभ।

कैसे बनता चरणामृत : तांबे के बर्तन में चरणामृतरूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है।

चरणामृत लेने के नियम : चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धाभक्तिपूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है।

चरणामृत सेवन के **चमत्कारिक फायदे** :

- शास्त्रों में कहा गया है- अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्। विष्णो पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।।

अर्थात : भगवान विष्णु के चरणों का अमृतरूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।

- चरणामृत का जल का सेवन करने से कभी भी कैंसर नहीं होगा और न ही किसी भी प्रकार का अन्य रोग।
- तुलसी का पौधा एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, बीमारियां दूर भागती हैं और शारीरिक द्रव्यों का संतुलन बना रहता है।
- आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है।
- आयुर्वेद के अनुसार यह पौरूष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है।
- तुलसी के इस रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता हैं।
- स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाने भी कारगर होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बिहार में महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर अलग-अलग सुर!

पटना। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने-अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन में आरजेडी के नेतृत्व को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है। सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माले के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे। नेतृत्व कांग्रेस करेगी। सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा, सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनका कोई भी नेता अकेला सक्षम है, निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और ना ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है। जो बिहार के हित में होगा वो निर्णय लेगी।

महागठबंधन में नीतीश की वापसी के सवाल पर भड़के तेजस्वी

पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी महागठबंधन में फिर से शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं था और गठबंधन अब केवल आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। बिहार में ओबीसी, ईबीसी, दलितों और आदिवासियों के लिए 65% आरक्षण लागू न किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यादव ने उस समय अपना आपा खो दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार का फिर से स्वागत किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भड़कते हुए पूछा कि आपको ये विचार कौन देता है? हम उनका स्वागत क्यों करेंगे? कोई प्रस्ताव नहीं है, बकवास मत कीजिए। लालू (यादव) और मेरे अलावा कोई भी प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत नहीं है, और कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। जेडीयू और आरजेडी के बीच पर्दे के पीछे की सांठगांठ की अफवाहें कुमार के राजनीतिक गलियारे में उतार-चढ़ाव के इतिहास की पृष्ठभूमि में चल रही हैं।

कोई जय श्री राम कहे तो जय शिवाजी-जय भवानी से दें जवाब

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में विभाजन पैदा करने और जहर घोलने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने समर्थकों से जय श्री राम के जवाब में जय शिवाजी और जय भवानी कहने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कोई भी जय श्री राम कहता है, उसे जय शिवाजी और जय भवानी भी कहना चाहिए। उन्होंने भाजपा के कार्यों का कड़ा विरोध किया और कहा कि उनका इरादा उनके सामाजिक प्रभाव को चुनौती देना है। अगर कोई जय श्री राम कहता है, तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी कहे बिना मत जाने दो। भाजपा ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को कड़ी चुनौती दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किया है। ठाकरे ने भाजपा के देशभक्तिपूर्ण रुख पर सवाल उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय खेलों पर उनके बदलते रुख का जिक्र किया।

बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा ऐलान

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की और कहा कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। 'शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी वादा किया कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बिहार गया था, तो मैंने कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और यह भी कि जीवन को हर तरह से आदर्श कैसे बनाया जाए। शाह ने कहा कि गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में उनका सम्मान, सुरक्षा और स्वागत है। मिथिला की भूमि रामायण और महाभारत के समय से ही बुद्धिजीवियों की भूमि रही है।

आरएसएस के खिलाफ ना बोलें हिंदू नाराज हो जाएंगे : दिग्गी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर लगातार चर्चा हो रही है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस के खिलाफ बोलने से मना किया गया था, क्योंकि इससे हिंदुओं के नाराज होने का डर था। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा एक दिन पहले राज्य में उन लोगों पर की गई सख्त टिप्पणी की सराहना की, जो पार्टी में सत्तारूढ़ भाजपा की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सिंह ने गांधी को उनके बयान के लिए बधाई दी और कहा, मुझे याद है कि जब मैं एमपी के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव प्रचार करने गुजरात गया था, तो मुझे आरएसएस के खिलाफ न बोलने की हिदायत दी गई थी। हिंदू नाराज हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम रहे राज्यसभा सांसद ने कहा कि आरएसएस के नेतृत्व वाला संघ परिवार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

धर्मेंद्र प्रधान के बेईमान वाले बयान पर बवाल, डीएमके के सांसदों का हंगामा

नई दिल्ली। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी जब द्रमुक सदस्यों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान ने तमिलनाडु सरकार को बेईमान बताते हुए कहा कि वह छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है और पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना पर पूरी तरह यू-टर्न ले रही है।

केंद्रीय मंत्री की इन टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए द्रमुक सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हालांकि, द्रमुक सांसदों ने उनकी अपील को नजरअंदाज किया और अपना विरोध जारी रखा।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई और लोकसभा में प्रश्नकाल का सामान्य तरीके से आरंभ हुआ, लेकिन पीएमश्री योजना को लेकर द्रमुक सांसद टी सुमति के पूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब के बाद द्रमुक सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

सुमति ने पीएमश्री योजना के तहत आरोप लगाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को स्वीकार नहीं करने के कारण तमिलनाडु को पीएमश्री योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि अन्य राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है।

उन्होंने कहा, 'मैं (शिक्षा) मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या स्कूली छात्रों की शिक्षा के लिए चिह्नित धन को राज्य के खिलाफ बदला लेने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सुमति ने कहा, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या वह संसद को आश्वासन देगी कि कानून के तहत जिस नीति को लागू नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार नहीं करने के लिए किसी भी राज्य को धन की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा?''

प्रधान की इस टिप्पणी पर हंगामा

पूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एक समय था जब तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के साथ (एनईपी पर) एमओयू पर हस्ताक्षर करने को तैयार थी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के साथ कुछ सदस्य हमारे पास आए थे और उन्होंने सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे गैर-भाजपा शासित राज्य भी पीएमश्री योजना को स्वीकार कर रहे हैं।

प्रधान ने कहा, हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे (द्रमुक) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने द्रमुक पर तमिलनाडु के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सबके लिए काम कर रही है।

प्रधान ने कहा, मेरी जानकारी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनईपी को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोक रहे हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री (स्टालिन) छात्रों के प्रति ईमानदार नहीं हैं।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों के हंगामे के बीच कुछ मिनट तक प्रश्नकाल संचालित किया। उन्होंने द्रमुक के सदस्यों से कहा, आपके सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका दिया गया। आप मंत्री का जवाब सुनें। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। यह गलत परंपरा है। संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें और कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अध्यक्ष ने कहा, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आप लोग अपनी सीटों पर जाएं और सदन को चलने दें। सदन आपका है और अच्छे उत्साह एवं उमंग के साथ आज की कार्यवाही शुरू हुई है। हंगामा नहीं रुका तो अध्यक्ष ने करीब आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा

राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग

नईदिल्ली। राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों पर संसदीय चर्चा की मांग की। आज यह मुद्दा लोकसभा में गूंजा है। राहुल गांधी ने सरकार से बड़ी मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर विपक्ष में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया से कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यानी सत्ता में बैठी पार्टी मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रही है।

महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया, अब बंगाल में भी उन्होंने यही शुरू कर दिया है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी...तो एक ही पार्टी सत्ता में आती रहेगी और वो भ्रष्टाचार भी करेगी। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग सरकार के हाथ में है... अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं... अगर यही व्यवस्था चलती रही तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि दिखावा है... हमें कई सालों से शक है... जमीन पर क्या होता है ये सबको पता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि मतदाता सूची में कुछ खामियां हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद और बर्दवान संसदीय क्षेत्रों और हरियाणा में एक ही ईपीआईसी (चुनावी फोटो पहचान पत्र) संख्या वाले मतदाता मौजूद हैं। टीएमसी ने कहा कि तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची पर चिंताओं को उठाने के लिए नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल रहा है। उन्होंने मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की भी मांग की, खास तौर पर अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले।

सौगत रॉय ने दावा किया, कुछ गंभीर खामियां हैं। महाराष्ट्र के मामले में यह बात कही गई है, जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई थी। हरियाणा में भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया। अब वे पश्चिम बंगाल और असम में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं।% तृणमूल नेता ने कहा, पूरी मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि सूचियों में कुछ गलतियां क्यों हुईं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों से सदन में प्रश्नकाल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लोकसभा सूत्रों ने बताया कि बिरला ने सोमवार को व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से प्रश्नकाल को सुचारू रूप से जारी रखने का आग्रह किया। प्रश्नकाल में आमतौर पर हंगामे के दृश्य देखने को मिलते हैं क्योंकि विपक्ष कई तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करता है।

संसद के दोनों सदनों ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार विजय का उल्लेख किया और कहा कि इस उपलब्धि से पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। बिरला ने कहा, ''यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे हैं।'' सदस्यों ने मेजें थपथपाकर भारतीय टीम को बधाई दी। राज्यसभा में भी भारतीय टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी गई।

विपक्ष को कराना पड़ेगा नियमों का रिफ्रेशमेंट कोर्स : जेपी नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जनता के बीच संसद की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश की संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के अंदर बहस करने की एक समुचित व्यवस्था है। इसमें नियमों के अनुसार बहस करने का आवेदन देकर लघु और लंबी चर्चा करने का प्रावधान है। लेकिन नियमों की जानकारी न रखते हुए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और जनता के बीच यह छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से भाग रही है। राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष को नियमों के अंतर्गत चर्चा कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष रहते हुए भी उन्होंने खूब बहस में भाग लिया और सबसे बेहतर विधायक का ईनाम भी जीता। लेकिन विपक्ष अब नियमों को नहीं जानना-समझना चाहता है और केवल बहिर्गमन कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। विपक्ष के रुख से नाराज नड्डा ने कहा कि विपक्ष जिस तरह नियमों की अवहेलना कर रहा है, ऐसा लगता है कि अब उन्हें नियमों की जानकारी देने के लिए एक रिफ्रेशमेंट कोर्स कराने की जरूरत आ गई है। यदि विपक्ष को नियमों की जानकारी होगी तब संभवत: इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव न हो।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी के अवॉर्ड समारोह में गायब रहा मेजबान पाकिस्तान

दुबई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीत ली है। लेकिन इसके समापन समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जब पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन दुबई में हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पीसीबी की तरफ से कोई भी मंच पर नहीं दिखा, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी सवाल उठाए हैं।

जब पूरा भारत चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था, तब दुबई से आई अवॉर्ड समारोह तस्वीर ने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। सवाल उठने लगे कि आखिर पीसीबी का कोई भी बड़ा नाम मंच पर क्यों नहीं दिखा? इस मुद्दे ने पाकिस्तान में भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं शोएब अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्हें इस मामले पर नराजागी जताते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि ये मेरी समझ से परे है। वर्ल्ड स्टेज पर ऐसा कैसे हो सकता है? पीसीबी चेयरमैन या कोई बड़ा अधिकारी वहां होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की गैरमौजूदगी को लेकर सफाई दी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, मोहसिन नकवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह दुबई नहीं जा सके। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुमेर अहमद और अधिकारी उस्मान वाला स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। सुमेर तो चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर थे, बावजूद उनकी गैरमौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 217 अंक नीचे तो निफ्टी 22,460 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार आज (10 मार्च) सप्ताह के पहले दिन ही गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 217.41 (0.29%) अंक गिरकर 74,115.17 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 92.20 (0.41%) अंक गिरकर 22,460.30 पर बंद हुआ। आज बाजार में 1147 शेयरों में बढ़त, जबकि 2776 शेयरों में गिरावट रही। इसके अलावा 140 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, ओएनजीसी, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। जबकि पावर ग्रिड कॉर्प, एचयूएल, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ और नेस्ले इंडिया आज बढ़त वाले शेयर रहें। पिछले कारोबारी सत्र शुक्रवार (7 मार्च) को घरेलू शेयर बाजार लगभग सपाट बंद हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 7.80 अंक या 0.03% बढ़कर 22,552.50 पर बंद हुआ था।

एक महीने में 15 प्रतिशत टूटा बैंकिंग शेयर

नईदिल्ली। इंडसइंड बैंक के शेयर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार (10 मार्च) को दबाव में रहे। बीएसई पर शुरुआती कारोबार में इंडसइंड बैंक का स्टॉक 5% से ज्यादा टूट गया। बैंक के शेयरों में गिरावट की ताजा वजह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का फैसला है। केंद्रीय बैंक ने सुमंत कठपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में केवल एक साल (23 मार्च 2026 तक) के लिए पुनर्नियुक्त किया, जबकि बैंक के बोर्ड ने उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी थी। इस वजह से इंडसइंड बैंक के शेयर को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है। पिछले एक महीने में इंडसइंड बैंक का स्टॉक 15% तक टूट गया है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है।

महारत्न पीएसयू ने दिया अपने चौथे डिविडेंड को लेकर अपडेट

नईदिल्ली। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), जो एक महारत्न कंपनी है, जल्द ही अपने निवेशकों के लिए बड़ी खबर ला सकती है। कंपनी ने 9 मार्च 2025 को बताया कि उसके निदेशक मंडल की मीटिंग 12 मार्च को होने वाली है। इस मीटिंग में दो अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पहला, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी बाजार से फंड जुटाने की योजना बनाएगी। इसके लिए बॉन्ड, टर्म लोन और कमर्शियल पेपर्स के जरिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से पैसा जुटाया जा सकता है। दूसरा, कंपनी 2024-25 के लिए चौथा अंतरिम डिविडेंड घोषित कर सकती है। अगर बोर्ड इसे मंजूरी देता है, तो निवेशकों को एक और डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। पीएफसी ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक तीन अंतरिम डिविडेंड दिए हैं। आखिरी बार 28 फरवरी 2025 को कंपनी ने रू. 3.50 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड दिया था।

आईएमएफ से कर्ज लेकर ब्रिक्स बैंक में निवेश करेगा पाकिस्तान!

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पिछले वर्ष पाकिस्तान को दी गई 7 अरब डॉलर की बेलआउट पैकेज की पहली समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच, भारत, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में लगभग 600 मिलियन डॉलर का निवेश करने की पाकिस्तान की योजना पर आपत्ति जताने के लिए तैयार है। भारत यह आपत्ति ऐसे समय में उठाएगा, जब कर्ज की दूसरी किस्त पर आईएमएफ बोर्ड विचार करेगा। भारत आमतौर पर आईएमएफ बोर्ड की बैठकों में पाकिस्तान के कर्ज अनुरोधों पर मतदान से बचता रहा है। हालांकि, जनवरी 2024 में जब आईएमएफ बोर्ड पाकिस्तान के 3 बिलियन स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (एसबीए) की समीक्षा कर रहा था, तब भारत ने आईएमएफ से सख्त निगरानी की मांग की थी।

प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनने की दौड़

मनीष तिवारी

भारत का अनुसंधान एवं विकास (आर.एंड डी.) क्षेत्र गहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, जो देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक कमजोरियों को दर्शाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर, भारत का आर.एंड डी. खर्च 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.83 प्रतिशत से घटकर आज मात्र 0.64 प्रतिशत रह गया है। निजी क्षेत्र का निवेश, जिसे कभी नवाचार का संभावित चालक माना जाता था, लगातार कम होता जा रहा है, जिससे संकट और बढ़ गया है। भारत वैश्विक आर.एंड डी. व्यय में सिर्फ 2.9 प्रतिशत का योगदान देता है, जो संयुक्त राज्य अमरीका (24.8प्रतिशत) और चीन (22.8प्रतिशत) से काफी पीछे है। यह दीर्घकालिक कम निवेश तकनीकी आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है और विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाता है। साहसिक सुधारों और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी के बिना, वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाएं मायावी बनी रहेंगी।

क्वांटम कम्प्यूटिंग में आगे निकलने के लिए संघर्ष = क्वांटम कम्प्यूटिंग तकनीकी नवाचार के अत्याधुनिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभूतपूर्व प्रसंस्करण शक्ति और एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा को बाधित करने की क्षमता प्रदान करता है। जबकि अग्रणी वैश्विक खिलाड़ियों ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, भारत की प्रगति सुस्त रही है। 2010 के उत्तरार्ध से, अमरीका, चीन और यूरोपीय संघ ने क्वांटम अनुसंधान पर अपना दबदबा बनाया है, जो सामूहिक रूप से 40 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के कुल निवेश का अधिकांश हिस्सा है। 2016 में क्वांटम

तकनीक को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने के बाद, अकेले चीन ने 2022 तक 15.3 बिलियन अमरीकी डालर देने की प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राज्य अमरीका ने राष्ट्रीय क्वांटम पहल अधिनियम (2018) के माध्यम से, महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र के योगदान के साथ, अवर्गीकृत निधि में 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर आबंटित किए हैं। इसकी तात्कालिकता को समझते हुए, भारत ने 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया, जिसमें 2023-2031 के लिए 6,000 करोड़ रुपए (लगभग 720 मिलियन अमरीकी डालर) निर्धारित किए गए। मिशन का लक्ष्य 8 वर्षों में 50-1,000 क्यूबिट वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कम्प्यूटर विकसित करना है, साथ ही क्वांटम संचार, सैंसिंग और सामग्रियों में प्रगति करना है। हालांकि, असंगत बजट आबंटन चिंता पैदा करते हैं। बी.ई. 2024-25 के लिए शुरूआती 427 करोड़ रुपये को बाद में घटाकर सिर्फ 86 करोड़ रुपए (आर.ई. 2024-25) कर दिया गया, इससे पहले बी.ई. 2025-26 के लिए इसे फिर से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

विशेषज्ञों का तर्क है कि सरकार का 50-1,000 क्यूबिट क्वांटम कम्प्यूटर विकसित करने का लक्ष्य पहले से ही पुराना हो चुका है। इसके बजाय, वे भारत के महत्वपूर्ण डिजिटल और संचार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए क्वांटम सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं। भारत क्वांटम कम्प्यूटिंग पेटेंट और अनुसंधान आऊटपुट में भी पीछे है। भारत शीर्ष 10 में नहीं है, जो मजबूत नवाचार नीतियों और क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए अधिक शोध-संचालित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, चीन ने 2023 में 276,288 औद्योगिक रोबोट स्थापित किए, जबकि भारत केवल 8,510 ही स्थापित कर पाया। यह अंतर न केवल उत्पादकता में बाधा डालता है, बल्कि अनुसंधान, विकास और तकनीकी एकीकरण में व्यापक कमजोरियों को भी दर्शाता है। प्यू रिसर्च सैंटर के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की निम्न-आय वाली 73 प्रतिशत आबादी स्वचालन के कारण नौकरी जाने का डर रखती है, जो आर्थिक असमानता के बारे में डूक्षचताओं को रेखांकित करता है। जबकि अन्य विकासशील देशों में भी इसी तरह की चिंताएं मौजूद हैं।

ईडी के छापे के बाद भूपेश बघेल की मीडिया से बातचीत

हमारे पास जो पैसा घर में है वह खेती और डेयरी का

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी अधिकारियों को मेरे निवास से कुछ नहीं मिला है। मेरे घर की तलाशी में मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बातचीत की पेनड्राइव मिली है। रमन सिंह के पुत्र अभिषाक सिंह के कंपनी के बांड पेपर मिला है, सीएम मैडम वाली फाईल पड़ा हुआ था, जिनका नाम सुनते ही उन्होंने छोड़ दिया यह पेपर नहीं ले गये। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिशें हो रही है। यह छापेमारी मुझे बदनाम करने का सुनियोजित षड़यंत्र था।

ईडी की यह छापेमारी प्रतिशोध के तहत की गई है। हम लोग यहा संयुक्त परिवार में रहते है। साथ ही हमारा व्यवसाय किसानी है। हम 140 एकड़ में खेती करते है। हमारे पास जो पैसा घर में है वह खेती और डेयरी व्यवसाय की आय का पैसा मिला है। हम लोग के पास से सिर्फ 33 लाख मिला है। ईडी द्वारा नोट गिनने की मशीन मंगाई गई ताकि मीडिया में प्रचारित हो की नोट गिनने की मशीन आयी बहुत पैसा मिला होगा। हमारे घर में जो सोना, गहने थे उसका पूरा हिसाब था उसे नहीं ले गये। जो कैश था उसका पूरा हिसाब है। मैंने विधानसभा में सवाल पूछा छापा मार दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विधानसभा में सवाल पूछना गलत हो गया है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा तो उनको जेल में डाल दिये। शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है अभी फाइनल रिपोर्ट तक समिट नही कर पाये है। विधानसभा में प्रश्न पूछा तो मेरे यहां छापेमारी हो गयी। सीडी कांड में मुझे बरी कर दिया गया तो भाजपा इससे बौखला गयी। जब बरी हुआ तो एक ही चीज मैंने कहा सत्यमेव जयते। लेकिन आज जिस प्रकार की कार्यवाही हुयी है इससे पता चलता भाजपा किसी भी सीमा तक जा सकती है। भाजपा के पास कुछ करने को नही है। देश में विपक्ष को परेशान और प्रताड़ित करने के लिये ऐसी हरकते करती है। पूर्व मुख्यमंत्री के यहां ईडी छापा मारने आयी है और कुछ घंटो में छापा समाप्त हो जाये तो समझ जाना चाहिये कि कुछ नही मिला। ईडी सिर्फ बदनाम करने के लिये आये थे प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। जिस प्रकार से मुझे एआईसीसी महासचिव एवं पंजाब का प्रभार दिया गया है इससे भाजपा घबरा गयी है। विधानसभा में सवाल भी पूछा इसलिये भाजपा बौखला गयी है और कार्यवाही के लिये भेज दिया। केवल बदनाम और षडयंत्र करना भाजपा का चरित्र है। ईडी सिर्फ परेशान करने के लिये आयी थी।

पूर्व सीएम बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम साव का पलटवार

ईडी के पास कुछ सबूत हैं, तभी तो वो कार्रवाई करने गई

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सोमवार को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की. इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव एप्प घोटाला, सीजी पीएससी घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ. इन घोटालों के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे. श्वष्ठ के पास कुछ साक्ष्य सबूत है, तभी तो वो कार्रवाई करने गई है.डिप्टी सीएम साव ने कहा कि ईडी किन विषयों के जांच कर रही है? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, सीजी पीएससी घोटाला जो कांग्रेस सरकार में हुए. ये घोटाले हुए कब? जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, जिस विषय की जांच श्वष्ठ कर रही है.

उन्होंने कहा कि यह जांच आज से शुरू नहीं हुई है. श्वष्ठ की जांच लंबे समय से चल रही है. जांच में जो श्वष्ठ को तथ्य मिलते हैं, उसके अनुसार वो आगे कार्रवाई करती है. जिनके-जिनके खिलाफ कोई तथ्य या सबूत आधार मिलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. जांच करने के लिए श्वष्ठ भूपेश बघेल के घर गयी है. इसलिए इसे राजनीतिक आधार बनाकर बोलना विधानसभा में प्रश्न उठाने पर कार्रवाई बोलना उचित नहीं है.

डिप्टी सीएम साव ने आगे कहा- देखिए कैसे गुमराह किया जाता है, सवेरे उनका कार्यालय कहता है कि पंजाब के प्रभारी बने हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है. जबकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सवाल उठाने पर कार्रवाई हो रही है. ईडी भेजे जा रहे हैं, तो इस तरह अलग-अलग बहाने मत करें, जनता को गुमराह न करें.

डिप्टी सीएम साव ने आगे कहा कि वास्तविकता ये है, ईडी घोटालों की जांच कर रही और उसी के आधार पर यह जांच कार्रवाई की है. श्वष्ठ को प्रकरण में जब किसी के खिलाफ कोई तथ्य मिलता है, सबूत होता है, या शिकायत के आधार पर तथ्य हो, तब तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई होती है. जब लगता है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उप निरीक्षक संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र

पुलिस जनता के विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक : साय

चार नए महिला थानों का उद्घाटन, पुलिस बल को और सशक्त बनाने पर जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में उप निरीक्षक संवर्ग के 840 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस बल की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण निर्मित हो, यह सुनिश्चित करना भी पुलिस विभाग की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का कार्य लोगों के बीच शांति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तकनीकी संसाधनों के समावेश से पुलिस बल को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्दी का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि समाज की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने नव नियुक्त पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे अपनी वर्दी का सम्मान करें और इसे हमेशा गर्व से धारण करें।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने जशपुर, रायगढ़, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में नए महिला थानों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन थानों के माध्यम से महिलाओं को अधिक सुरक्षित वातावरण और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं पर विचार कर रही है। इन योजनाओं के तहत तकनीकी उन्नयन, आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है।

ईडी की कार्यवाही भाजपा की हताशा : दीपक बैज

रायपुर। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्यवाही भाजपा की हताशा को दिखाता है। भाजपा, कांग्रेस और भूपेश बघेल से डरी हुई है। पिछले दिनों भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाये जाने के बाद पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में राजनैतिक वातावरण बना है उससे भाजपा डरी हुई है। पिछले हफ्ते ही भाजपा और सीबीआई का एक षड्यंत्र अदालत में धाराशाई हुआ है, भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का फैसला आया इन सब घटनाक्रम से भाजपा बौखला गयी है। बौखलाहट में भाजपा ने ईडी को भेजा है।पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। सात साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया, अब दुर्भावनापूर्वक ईडी को मोहरा बना कर भेजा गया है।

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक विफलता अमेरिका मामले में उसकी कूटनीतिक विफलता से पूरे देश में मोदी सरकार की जगहसाई हो रही है, अपनी राजनैतिक विफलता से तथा देश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के घर ईडी को भेजा है। ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर पहुंचना जांच नहीं है।

भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डर कर भाजपा ने ईडी को भेजा

रायपुर। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने के कारण भाजपा का षड़यंत्र बेनक़ाब होने के बाद बौखलाई भाजपा ने भूपेश बघेल के घर ईडी को भेजा है।श्री भूपेश बघेल से भाजपा का डर कोई नया नहीं है। ज़ब वो पीसीसी अध्यक्ष थे तब रमन सरकार उनके पीछे राज्य की एजेंसियो को लगा कर रखी थी।

उनके पैतृक गांव में खेत को नापने रमन सरकार ने भरी बरसात में राजस्व का पूरा दल भेजा था तथा भिलाई स्थित उनके मकान को नापने के लिए दल भेजा। उनको, उनकी स्व माता जी, पत्नी को ई ओ डब्ल्यू में बैठाया। उनके खिलाफ सीडी का झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। सीडी मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाया जिसमें सीबीआई की अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया।

उनके पुत्र को आधारहीन मामले पूछताछ करने थाने बुलवाया। मुख्यमंत्री रहते बदनाम करने उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड मरवाया। एक ड्राइवर के कथित बयान के आधार पर उनके खिलाफ ईडी ने आधारहीन प्रेस नोट जारी कर महादेव एप्प मामले में झूठा आरोप लगाया। सरकार जाने पर ईओडब्ल्यू में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। अब ईडी को उनके निवास पर भेजा है। भाजपा भूपेश बघेल से डरती है। उनके पंजाब प्रभारी बनने और सीबीआई अदालत से बरी होने के बाद यह नया षड्यंत्र किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.